Kamal.Sandesh
kamalsandesh.org
KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-09
01-15 मई, 2025 (पाक्षिक)
₹20

'ओडिशा के लगभग 3.52 करोड़ लोग एबी-पीएमजेवाई के अंतर्गत कवर किए जाएंगे'

'भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा'

नई दिल्ली में 14 अप्रैल, 2025 को 'भारत रत्न' डॉ. बीआर अंबेडकर की जयंती पर उनके महापरिनिर्वाण स्थल, 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

नई दिल्ली में 10 अप्रैल, 2025 को लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

कटक (ओडिशा) में 11 अप्रैल, 2025 को लाभार्थियों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के सह-ब्रांडेड कार्ड वितरित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि पर 12 अप्रैल, 2025 को 'शिवराज्याभिषेक' से लेकर 'हिंदवी स्वराज' की स्थापना तक के गौरवशाली इतिहास के साक्षी ऐतिहासिक रायगढ़ किले का भ्रमण करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण

चेन्नई (तमिलनाडु) में 12 अप्रैल, 2025 को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेतागण

संभाजीनगर (महाराष्ट्र) में 18 अप्रैल, 2025 को मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महान योद्धा राजा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा: प्रधानमंत्री**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये...

09 **'विकसित भारत' के लिए 'विकसित हरियाणा', यही हमारा संकल्प है: नरेन्द्र मोदी**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न...

11 **भारत आज 'विकास और विरासत' दोनों को एक साथ आगे बढ़ा रहा है**
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3,880 करोड़ ...

13 **यह कांग्रेस सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और कुप्रबंधित सरकारों में से एक है : जगत प्रकाश नड्डा**
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने...

14 **इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाएगा: नरेन्द्र मोदी**
जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में 22 अप्रैल, 2025 को हमेशा एक काले दिन...

लेख

मेरे अटल जी/ **नरेन्द्र मोदी** 22

बाबासाहेब आंबेडकर: राष्ट्र सर्वप्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के अग्रदूत/ **राजनाथ सिंह** 28

बाबासाहेब आंबेडकर: सर्व समावेशी समाज की स्थापना से सशक्त भारत के निर्माण तक/ **तरुण चुग** 30

अन्य

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले छह साल में सबसे निचले स्तर पर 16

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल निर्यात 5.50 प्रतिशत बढ़कर 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान 18

स्वतंत्र भारत में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पार 19

'नेशनल हेराल्ड का मामला धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है' 20

कमल पुष्प 21

भारत-सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदारी से और मजबूत हुए 24

शिवाजी महाराज का मतलब स्वाभिमान और स्वराज की अमर जिजीविषा है: अमित शाह 26

'आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी' 27

दिल्ली में 36 लाख लोगों को एबी पीएम-जेएवाई योजना का लाभ मिलेगा: जगत प्रकाश नड्डा 32

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

हमारी सरकार बाबासाहेब की आकांक्षाओं के अनुरूप गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर रही है, वहीं कांग्रेस ने उनके विचार और उनकी पहचान को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास किया।

(14 अप्रैल, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में 6 एम्स बने थे, इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 नये एम्स बने। आज विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी सरकार सुलभ करा रही हैं।

(15 अप्रैल, 2025)

अमित शाह

जब आजादी की शताब्दी का इतिहास लिखा जाएगा, सबसे पहले सुरक्षा बलों के अमर शहीदों की वीरता की गाथा स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी।

(17 अप्रैल, 2025)

राजनाथ सिंह

हम बेहद मजबूती के साथ, सुनियोजित तरीके से, आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा क्षेत्र के निर्माण की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

(17 अप्रैल, 2025)

बी.एल. संतोष

श्री नयनार नागेंद्रन को तमिलनाडु, भाजपा का सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई! तमिलनाडु की राजनीति में आपका विस्तृत अनुभव तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण प्रदेश में पार्टी के विस्तार के एक नए युग की शुरुआत करेगा।

(12 अप्रैल, 2025)

धर्मेंद्र प्रधान

नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता विदेश में जाकर चुनाव आयोग पर बेबुनियाद और निराधार टिप्पणी करते हैं...आज स्पर्धा की ये राजनीति देश की संवैधानिक संस्थाओं को चोट पहुंचा रही है।

(23 अप्रैल, 2025)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
बुद्ध पूर्णिमा (12 मई)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

संपादकीय

राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़ा है

जम्मू-कश्मीर में पहलगाम के पास वैसरन घाटी में हुए कायरतापूर्ण आंतकी हमले की पूरे विश्व में कड़ी भर्त्सना हुई है। यह न केवल आतंकियों द्वारा अत्यंत नीचतापूर्ण कृत्य है बल्कि पूरी मानवता के विरुद्ध एक घृणास्पद अपराध है। निर्दोष पर्यटकों को धर्म के आधार पर चुन-चुन कर निशाना बनाना एक बार पुनः आतंकियों के भयानक चेहरे एवं कुत्सित इरादे को दर्शाता है, जिसे कोई भी सभ्य समाज सहन नहीं कर सकता। जहां सुरक्षा बलों ने पूरे जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों को निशाने पर लेते हुए तलाशी अभियान शुरू किया है, एक राष्ट्र के रूप में आतंकवाद से लड़ने का भारत का संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। पूरा देश इस निंदनीय हमले में प्राण गंवाने वाले बलिदानी एवं उनके परिवारों के साथ आज एकजुट खड़ा है। इस नृशंस हमले के पीछे के आतंकियों के प्रति 'कड़ी कार्रवाई' के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के साथ संपूर्ण राष्ट्र आज आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट खड़ा है।

ध्यान देने योग्य है कि जम्मू-कश्मीर जो पूर्व में पूरी तरह से आतंकवाद से त्रस्त था, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ एवं ऊर्जावान नेतृत्व में 2014 से व्यापक परिवर्तन का साक्षी रहा है। पिछले दशक में मोदी सरकार ने सक्रियतापूर्ण सैन्य कार्यवाहियों, पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर अलग-थलग कर तथा बड़े संवैधानिक सुधारों द्वारा जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद एवं कुव्यवस्था से निकालकर एक सुस्थिर एवं विकासोन्मुखी क्षेत्र बना दिया है। पत्थरबाजी, बमबाजी एवं आतंकवाद के काले दिन लगभग समाप्त हो चुके हैं। कश्मीर में आम जन की हिंसक घटनाओं में मृत्यु अब 81 प्रतिशत कम हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निरंतर प्रयासों के कारण आतंकवादी संबंधी गतिविधियों में 71 प्रतिशत कमी, सामान्यजन की मृत्यु में 81 प्रतिशत तथा सैन्य बलों की क्षति में 48 प्रतिशत की कमी हुई है। जम्मू-कश्मीर में 2006 से 2013 के मध्य 4,766 आतंकी घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं। 2010 में 6,235 आमजन पत्थरबाजी में घायल हुए जिसकी संख्या अब शून्य है। मोदी सरकार ने आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया, जबकि ठीक इसके विपरीत कांग्रेसनीत यूपीए काल में 2004 से 2014 के बीच 6,000 लोग आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। 2014 से अब तक पूरे देश में आतंकवादी घटनाओं में 81 प्रतिशत कमी आयी है। 2010 में 1,936 घटनाएं हुई थीं, जिसकी संख्या 2024 में मात्र 374 है और इसका सबसे अधिक लाभ जम्मू-कश्मीर को मिला है। इस व्यापक परिवर्तन में धारा-370 के निरस्तीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे घाटी में शांति एवं सुरक्षा तो स्थापित हुई ही, साथ ही जमीनी स्तर पर जन-जन की भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हुई है। जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार के साथ-साथ पंचायत एवं नगरपालिका स्तर पर 36,000 से भी अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधि आज अपने अधिकारों का उपयोग कर जनता का सशक्तीकरण कर रहे हैं। इससे ग्रास-रूट स्तर पर लोकतंत्र अभूतपूर्व रूप से सुदृढ़ हुआ है। यही कारण है कि आतंकी समूह और सीमापार के उनके सहयोगी के हाथ-पैर फूल गए हैं एवं वे लगातार क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को भंग करने का कुप्रयास कर रहे हैं।

> **पहलगाम नृशंस हमले के पीछे के आतंकियों के प्रति 'कड़ी कार्रवाई' के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के साथ संपूर्ण राष्ट्र आज आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट खड़ा है**

पहलगाम में हुए अत्यंत घृणित आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में मोदी सरकार ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को 23 अप्रैल, 2025 से रोक दिया है। इससे पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। साथ ही, कई स्तर पर राजनयिक कदम उठाये जा रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा सेवा रद्द कर दी गई है तथा भारत में रह रहे पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तान की मुख्य सीमा बंद कर दी गई है तथा पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या में भारी कमी की गई है। प्रोपगेंडा एवं भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यू-ट्यूब चैनल तथा डॉन न्यूज एवं जियो न्यूज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है जो आतंकियों को प्रशिक्षित कर हथियार देकर विश्व के दूसरे देशों में निर्यात करता है। यह पूरी दुनिया के आतंकियों के लिए एक सुरक्षित शरण-स्थली बन चुका है। आज जब भारत देश के भीतर एवं बाहर दोनों ओर आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है तथा हर वैश्विक मंच पर अपनी आवाज उठा रहा है, अब समय आ गया है कि पूरा विश्व आंतकवाद के खात्मे के लिए एकजुट हो जाए। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगाः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री का मधुबनी (बिहार) दौरा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में किए गए हमलों में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखने और प्रार्थना करने की अपील की। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश व्यथित है और शोकाकुल परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरा देश मिथिला और बिहार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के उद्देश्य से हजारों करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर मधुबनी में कहा कि बिहार वह भूमि है, जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। उन्होंने महात्मा गांधी के इस दृढ़ विश्वास की ओर ध्यान दिलाया कि भारत का तीव्र विकास तभी संभव है जब इसके गांव मजबूत हों। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पंचायती राज की अवधारणा इसी भावना में निहित है। उन्होंने कहा, "बीते दशक में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। पंचायतों को मजबूत बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले एक दशक में 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ी हैं।"

श्री मोदी ने बताया कि गांवों में 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायतों के डिजिटलीकरण से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों तक आसान पहुंच जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के दशकों बाद देश को एक नया संसद भवन मिला है, वहीं देश भर में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पंचायतों ने सामाजिक

‘भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा’

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों द्वारा निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरा देश व्यथित है और शोकाकुल परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि उपचार करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। श्री मोदी ने परिवारों को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डाला, जहां कुछ ने अपने बेटे, भाई या जीवन साथी खो दिए।

उन्होंने कहा कि पीड़ित विभिन्न भाषायी और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से थे— कुछ बंगाली, कन्नड़, मराठी, ओडिया, गुजराती बोलते थे और कुछ बिहार से थे। यह बताते हुए कि कारगिल से कन्याकुमारी तक इस हमले पर पूरे देश में समान रूप से दुःख और आक्रोश है, श्री मोदी ने कहा कि यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर एक निर्लज्ज हमला था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की, “इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से परे सजा मिलेगी।”

आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय

श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि आतंकवाद के बचे हुए गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने जोर देकर कहा, “140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति अब आतंकवाद के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी।”

प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से घोषणा करते हुए कहा कि भारत हर आतंकवादी, उसके आकाओं और उसके समर्थकों की पहचान करेगा, उन्हें ट्रैक करेगा और उन्हें दंडित करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत उन्हें धरती के कोने-कोने तक खदेड़ देगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा, “आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी और आतंकवाद को दंडित किया जाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ इस संकल्प के प्रति दृढ़ है।”

श्री मोदी ने यह भी कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इस मुश्किल समय में भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों और नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने इस मुश्किल समय में भारत का साथ दिया।

भागीदारी को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिक भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होता है। इस दृष्टिकोण को दर्शाते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून भी बनाया गया है।

श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण दिया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में कोई भी परिवार बेघर न रहे और सभी के सिर पर पक्की छत हो। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। श्री मोदी ने बताया कि अकेले बिहार में 57 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं।

बीता दशक: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का दशक

प्रधानमंत्री ने कहा, “बीता दशक, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का दशक रहा है।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ‘विकसित भारत’ की नींव को मजबूत कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल के पानी के कनेक्शन मिले हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 करोड़ से अधिक घरों में बिजली पहुंच चुकी है और

जिन लोगों ने कभी गैस चूल्हे पर खाना पकाने की कल्पना भी नहीं की थी, उन्हें अब गैस सिलेंडर मिल गए हैं।

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एम्स जैसे संस्थान कभी दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब दरभंगा में एम्स की स्थापना की जा रही है और पिछले एक दशक में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है।

श्री मोदी ने कहा कि जन औषधि केंद्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत बन गए हैं, जो 80 प्रतिशत छूट पर दवाइयां उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब 800 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जिससे लोगों को चिकित्सा व्यय में 2,000 करोड़ रुपये की बचत हो रही है।

एम्स जैसे संस्थान कभी दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित थे। अब दरभंगा में एम्स की स्थापना की जा रही है और पिछले एक दशक में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है

उन्होंने पटना और जयनगर के बीच 'नमो भारत रैपिड रेल' सेवा शुरू करने की घोषणा की, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और इस बात पर जोर दिया कि इस विकास से समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और बेगूसराय के लाखों लोगों को लाभ होगा। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दरभंगा हवाई अड्डे से मिथिला और बिहार में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है और पटना हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "ये विकास परियोजनाएं बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं।"

किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

श्री मोदी ने कहा, "किसान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, यह रीढ़ जितनी मजबूत होगी, गांव उतना ही मजबूत होगा और परिणामस्वरूप, राष्ट्र भी मजबूत होगा।" उन्होंने मिथिला और कोसी क्षेत्रों में बाढ़ की लगातार चुनौतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार बिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार है।

श्री मोदी ने कहा, "मिथिला का सांस्कृतिक प्रधान खाद्य पदार्थ मखाना अब सुपरफूड के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है।" उन्होंने बताया कि मखाना को जीआई टैग दिया गया है, जो इसे आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र के उत्पाद के रूप में प्रमाणित करता है। श्री मोदी ने कहा कि मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है।

इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, श्री जीतन राम मांझी, श्री गिरिराज सिंह, श्री चिराग पासवान, श्री नित्यानंद राय, श्री राम नाथ ठाकुर, डॉ. राज भूषण चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ■

प्रधानमंत्री ने 14 साल पहले शपथ लेने वाले रामपाल कश्यप से की मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा के यमुनानगर में कैथल के श्री रामपाल कश्यप से मुलाकात की। श्री मोदी को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि श्री कश्यप ने 14 साल पहले शपथ ली थी कि वे प्रधानमंत्री के चुनाव जीतने के बाद उनसे मिलने तक जूते नहीं पहनेंगे। उन्होंने नागरिकों से सामाजिक कार्य और राष्ट्र निर्माण से जुड़े सार्थक कार्यों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने का आग्रह किया।

एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, "हरियाणा के यमुनानगर में आज कैथल के रामपाल कश्यप जी से मिलने का सौभाग्य मिला। इन्होंने 14 वर्ष पहले एक व्रत लिया था कि 'मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और मैं उनसे मिल नहीं लेता, तब तक जूते नहीं पहनूंगा।' मुझे आज उनको जूते पहनाने का अवसर मिला। मैं ऐसे सभी साथियों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, परंतु मेरा आग्रह है कि वो इस तरह के प्रण लेने के बजाए किसी सामाजिक अथवा देशहित के कार्य का प्रण लें।" ■

'विकसित भारत' के लिए 'विकसित हरियाणा', यही हमारा संकल्प है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हरियाणा के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने हरियाणा की पवित्र भूमि को नमन किया और इसे मां सरस्वती का उद्गम, मंत्र देवी का निवास स्थल, पंचमुखी हनुमान जी का स्थान और पवित्र कपाल मोचन साहिब का स्थल बताया। उन्होंने कहा, "हरियाणा संस्कृति, भक्ति और समर्पण का संगम है।"

उन्होंने बाबासाहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और बाबासाहेब के विज़न और प्रेरणा पर प्रकाश डाला, जिससे विकास की दिशा में भारत की यात्रा को मार्गदर्शन मिल रहा है।

श्री मोदी ने कहा, "यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भारत के औद्योगिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक के उद्योगों के साथ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।"

> यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि भारत के औद्योगिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक के उद्योगों के साथ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है

इस बात को रेखांकित करते हुए कि केंद्र और राज्य सरकारों के तीसरे कार्यकाल के तहत हरियाणा लगातार विकास की दोगुनी गति देख रहा है, प्रधानमंत्री ने 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में विकसित हरियाणा के प्रति संकल्प पर जोर दिया।

औद्योगिक विकास 'सामाजिक न्याय' का मार्ग

बाबासाहेब अंबेडकर के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर गर्व व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने बाबासाहेब के इस विश्वास पर प्रकाश डाला कि औद्योगिक विकास सामाजिक न्याय का मार्ग होता है। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब ने भारत में खेतों के छोटे रकबे से जुड़े मुद्दे की पहचान की और इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त कृषि भूमि की कमी वाले दलितों को औद्योगीकरण से सबसे अधिक लाभ होगा।

श्री मोदी ने बाबासाहेब के विज़न को साझा किया कि उद्योग दलितों के लिए अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। उन्होंने भारत के औद्योगीकरण प्रयासों में बाबासाहेब की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया, जिन्होंने इस दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के साथ मिलकर काम किया था।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी औद्योगीकरण और विनिर्माण के बीच तालमेल को ग्रामीण समृद्धि की नींव के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने छोटू राम जी की इस विश्वास को रेखांकित किया कि गांवों में सच्ची समृद्धि तभी आएगी, जब किसान कृषि के साथ-साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाएंगे।

श्री मोदी ने आगे कहा कि चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने अपना जीवन गांवों और किसानों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया, भी इसी तरह का दृष्टिकोण साझा करते थे। उन्होंने चरण सिंह जी के इस दृष्टिकोण पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास को कृषि का पूरक होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं।

मिशन विनिर्माण

इस बात पर जोर देते हुए कि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' का सार विनिर्माण को बढ़ावा देने में निहित है, श्री मोदी ने विनिर्माण पर सरकार के विशेष ध्यान को रेखांकित किया, जो इस वर्ष के बजट में 'मिशन विनिर्माण' की घोषणा से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा, "मिशन का उद्देश्य दलित, पिछड़े, वंचित और हाशिए

के युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित करना, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यावसायिक लागत कम करना, एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना, उद्योगों को आधुनिक तकनीक से लैस करना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय उत्पाद विश्व स्तरीय हों।"

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए और आज के आयोजन के महत्व को उजागर करते हुए श्री मोदी ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम ताप विद्युत संयंत्र की तीसरी इकाई पर काम शुरू करने की घोषणा की, जिससे यमुनानगर और हरियाणा को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत ने अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना कर लिया है और अब पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करता है। उन्होंने हरियाणा में बिजली उत्पादन पर उनकी सरकार के विशेष ध्यान के लाभों पर प्रकाश डाला, जो वर्तमान में 16,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। उन्होंने आने वाले वर्षों में इस क्षमता को बढ़ाकर 24,000 मेगावाट करने के लक्ष्य की भी घोषणा की।

ताप विद्युत संयंत्र में निवेश करने और नागरिकों को खुद बिजली उत्पादक बनने के लिए सशक्त बनाने से जुड़े सरकार के दोहरे दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ़्त बिजली योजना के शुभारंभ का उल्लेख किया, जिससे लोग अपनी छतों पर सौर पैनल लगा सकते हैं, बिजली बिलों को समाप्त कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है, जिसमें हरियाणा के लाखों लोगों ने आवेदन किया है।

प्रधानमंत्री ने हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला

हवाई यात्रा को सभी के लिए सुरक्षित, किफायती और सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, जिस पर 410 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा, "आज पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज संविधान निर्माता बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती है।"

श्री मोदी ने अपने वादे को दोहराते हुए कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में उड़ेंगे, जो सपना अब पूरे देश में साकार हो रहा है, इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 10 वर्षों में लाखों भारतीयों ने पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव किया है। उन्होंने कहा कि नए हवाई अड्डे उन क्षेत्रों में भी बनाए गए हैं जहां पहले उचित रेलवे स्टेशन नहीं थे। श्री मोदी ने बताया कि 2014 से पहले भारत में 74 हवाई अड्डे थे, यह संख्या 70 वर्षों में हासिल हुई जबकि आज हवाई अड्डों की संख्या 150 से अधिक हो गई है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उड़ान योजना के तहत लगभग 90 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, जिसमें 600 से अधिक मार्ग चालू हैं, जिससे कई लोगों के लिए सस्ती हवाई यात्रा संभव हो गई है। श्री मोदी ने कहा, "हिसार हवाई अड्डा हरियाणा के युवाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाएगा तथा उन्हें नए अवसर और सपने प्रदान करेगा।" ■

मुद्रा योजना: 33 लाख करोड़ रुपये के गिरवी-मुक्त ऋण वितरित

प्रधानमंत्री ने छोटे शहरों में छोटे उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली और वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने पर सरकार के विशेष ध्यान को रेखांकित किया। उन्होंने मुद्रा योजना की 10 साल पूरे होने की उपलब्धि का उल्लेख किया, जिसके तहत 33 लाख करोड़ रुपये के गिरवी-मुक्त ऋण संवितरित किए गए हैं। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना के 50% से अधिक लाभार्थी एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों से हैं।

हरियाणा के किसानों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए, जो हर भारतीय की भोजन की थाली में योगदान देते हैं, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों की खुशियों और चुनौतियों के दौरान एक दृढ़ भागीदार के रूप में खड़ी हैं। उन्होंने हरियाणा के किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला, राज्य सरकार अब एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद करती है। श्री मोदी ने साझा किया कि हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से लाभ हुआ है, इस योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावे पेश किए गए हैं।

प्रधानमंत्री ने विकास के पथ पर हरियाणा की तीव्र प्रगति को रेखांकित करते हुए हिसार की अपनी पिछली यात्रा का उल्लेख किया, जहां अयोध्या धाम के लिए सीधी उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया गया था। उन्होंने रेवाड़ी के लिए नए बाईपास की भी घोषणा की, जिससे बाजारों, चौराहों और रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात की भीड़ कम होगी और वाहन आसानी से शहर से होकर गुजर सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि चार लेन वाला बाईपास दिल्ली और नारनौल के बीच यात्रा अवधि को एक घंटे कम कर देगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए लोगों को बधाई दी।

इस बात पर जोर देते हुए कि उनके लिए राजनीति सेवा का माध्यम है - लोगों और राष्ट्र की सेवा; श्री मोदी ने कहा, "हमारी पार्टी अपने वादों को पूरा करती है, जैसाकि हरियाणा में स्पष्ट है, जहां सरकार तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद अपने वादों को पूरा कर रही है।" ■

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं उद्घाटन

भारत आज 'विकास और विरासत' दोनों को एक साथ आगे बढ़ा रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने काशी से अपने गहरे जुड़ाव की चर्चा करते हुए अपने परिवार और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया और उन्हें मिले अपार स्नेह और समर्थन को भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने इस स्नेह के प्रति ऋणी होने का भाव प्रकट करते हुए कहा कि काशी उनकी है और वे काशी के हैं।

काशी अब न केवल प्राचीन है बल्कि प्रगतिशील भी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि काशी ने आधुनिकता को अपनाते हुए न सिर्फ अपनी विरासत को संजोया है बल्कि उज्ज्वल भविष्य को भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि काशी अब न केवल प्राचीन है बल्कि प्रगतिशील भी है, यह अब पूर्वांचल के आर्थिक मानचित्र का केंद्र भी है।

कार्यक्रम में काशी और पूर्वांचल के विभिन्न हिस्सों से जुड़ी कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से सम्पर्क को मजबूत बनाने, हर घर में नल से जल पहुंचाने के अभियान और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेल सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया। उन्होंने हर क्षेत्र, हर परिवार और हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि ये पहल पूर्वांचल को एक विकसित क्षेत्र में बदलने में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होंगी।

प्रधानमंत्री ने आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर समाज के कल्याण और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनके और सावित्रीबाई फुले के आजीवन समर्पण को याद किया। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए उनके दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों पर भी चर्चा की।

श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चलती है। उन्होंने पूर्वांचल के पशुपालक परिवारों, विशेषकर परिश्रमी महिलाओं को बधाई दी, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि जब-जब महिलाओं पर भरोसा किया जाता है, तब-तब उन्होंने इतिहास रच दिया है।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी प्लांट से जुड़े पशुपालक परिवारों को बोनस के वितरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपये से अधिक का यह बोनस कोई उपहार नहीं बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का पुरस्कार है, जो उनके श्रम और दृढ़ता के मूल्य को दर्शाता है।

> भारत पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है। इस सफलता का श्रेय लाखों किसानों और पशुपालकों को जाता है। ऐसी उपलब्धियां पिछले दस वर्षों में निरंतर प्रयासों का परिणाम हैं

काशी में हजारों परिवारों के जीवन और नियति को नया आकार देने वाली बनास डेयरी के परिवर्तनकारी प्रभाव की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि किस प्रकार से डेयरी ने कड़ी मेहनत को पुरस्कृत किया है और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं। उन्होंने गर्व से कहा कि इन प्रयासों ने पूर्वांचल की कई महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने में सक्षम बनाया है और अब वे आजीविका की चिंताओं से समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह प्रगति केवल बनारस और उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में स्पष्ट है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में दूध उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय लाखों किसानों और पशुपालकों को देते हुए कहा कि ऐसी उपलब्धियां पिछले दस वर्षों में निरंतर प्रयासों का परिणाम हैं। श्री मोदी ने डेयरी क्षेत्र को मिशन

मोड में आगे बढ़ाने के लिए की गई पहलों की ओर इशारा किया, जिसमें पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधाओं से जोड़ना, ऋण सीमा बढ़ाना और सब्सिडी कार्यक्रम का शुभारंभ शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कई वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड वितरित करने का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके चेहरों पर दिख रहे संतोष के भाव बताते हैं कि यह इस योजना की सफलता का प्रमाण है।

पिछले एक दशक में स्वास्थ्य सेवा में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल अस्पतालों की संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि रोगियों का उपचार भी पूर्ण गरिमा के साथ किया जा रहा है। श्री मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को गरीबों के लिए वरदान बताया, जो न केवल उपचार प्रदान करती है, बल्कि आत्मविश्वास भी जगाती है।

उन्होंने कहा कि वाराणसी में हजारों और पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को इस योजना से लाभ हुआ है और हर उपचार, ऑपरेशन और राहत उनके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के करोड़ों रुपये बचाए हैं, क्योंकि सरकार ने उनके स्वास्थ्य सेवा की जिम्मेदारी ली है।

वाराणसी में सबसे अधिक वय वंदना कार्ड

वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क इलाज के अपने वादे के साथ आयुष्मान वय वंदना योजना के शुभारंभ की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह पहल 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करती है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि वाराणसी ने सबसे अधिक वय वंदना कार्ड जारी किए हैं, यहां लगभग 50,000 कार्ड वितरित किए गए हैं।

क्षेत्र में बेहतर यातायात सम्पर्क को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चौड़ी सड़कों के साथ गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जैसे शहरों में यात्रा तेज़ और सुविधाजनक हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि कभी ट्रैफिक जाम से त्रस्त रहने वाले क्षेत्र अब विकास की गति देख रहे हैं। उन्होंने वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने के लिए पिछले एक दशक में हुए लगभग 45,000 करोड़ रुपये के निवेश का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस निवेश ने न केवल बुनियादी ढांचे को बल्कि विश्वास को भी बदल दिया है, जिससे काशी और पड़ोसी जिलों को लाभ हुआ है।

विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाने की भारत की यात्रा की चर्चा के साथ-साथ काशी को इस मॉडल का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने गंगा के प्रवाह और भारत की चेतना पर भी अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि काशी भारत की आत्मा और विविधता का सबसे सुंदर प्रतिनिधित्व है।

विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाने की भारत की यात्रा की चर्चा के साथ-साथ काशी को इस मॉडल का सबसे बेहतरीन उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने गंगा के प्रवाह और भारत की चेतना पर भी अपने भाव प्रकट करते हुए कहा कि काशी भारत की आत्मा और विविधता का सबसे सुंदर प्रतिनिधित्व है

जीआई टैगिंग में उत्तर प्रदेश अग्रणी

देश भर में जीआई टैगिंग में उत्तर प्रदेश की अग्रणी स्थिति को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने राज्य की कला, शिल्प और कौशल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मान्यता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी और उसके आसपास के जिलों के 30 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिले हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह टैग वस्तुओं की पहचान का पासपोर्ट हैं। उन्होंने क्षेत्र के उन उत्पादों को सूचीबद्ध किया जिन्हें मान्यता दी गई है, जैसे वाराणसी का तबला, शहनाई, दीवार पेंटिंग, ठंडाई, भरवां लाल मिर्च, लाल पेड़ा और तिरंगा बर्फी।

श्री मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि जौनपुर की इमरती, मथुरा की सांझी कला, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, प्रयागराज की मूंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठकला और लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी जैसे उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी की खुशबू अब सीमाओं को पार कर रही है और अपनी विरासत को दूर-दूर तक फैला रही है।

मुख्य बातें

- पिछले 10 वर्षों में बनारस के विकास को नई गति मिली है
- महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी ने महिला सशक्तीकरण, उनके आत्मविश्वास और समाज के कल्याण के लिए जीवन भर कार्य किया
- बनास डेयरी ने काशी के हजारों परिवारों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है
- काशी अब आरोग्य की राजधानी बन रही है
- आज काशी जाने वाला हर व्यक्ति यहां के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की प्रशंसा करता है
- उत्तर प्रदेश अब सिर्फ संभावनाओं की भूमि नहीं, बल्कि सामर्थ्य और सिद्धियों की संकल्प भूमि बन रहा है ■

श्री मोदी ने कहा कि काशी को संरक्षित करने का अर्थ भारत की आत्मा की रक्षा करना है। प्रधानमंत्री ने काशी को निरंतर सशक्त बनाने, इसे सुंदर बनाए रखने तथा इसकी प्राचीन भावना को आधुनिक पहचान के साथ जोड़ने की सामूहिक प्रतिबद्धता पर बल देते हुए अपने संबोधन का समापन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। ■

यह कांग्रेस सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और कुप्रबंधित सरकारों में से एक है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 अप्रैल, 2025 को हिमाचल प्रदेश स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश की सुस्त सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मगर उसका दोष केंद्र सरकार पर मढ़ने का प्रयास कर रही है। मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के कई कल्याणकारी योजनाओं के पैसे आवंटित कर चुकी है, मगर कुम्भकर्णी नींद में सोई कांग्रेस सरकार उन योजनाओं के लिए जमीन तक आवंटित नहीं कर पाई है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार से दुःखी है और आने वाले समय में वह अपना जवाब भी देगी। प्रेस वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राजीव बिंदल, सांसद श्री राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

कांग्रेस खुद अपनी नालायकी के कारण सरकार चला नहीं पा रही और दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रही है

केंद्र सरकार का सहयोग

श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश के सालभर के विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने 11,806 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। टैक्स रिवेन्यू शेयर के तहत हिमाचल को 10,681 करोड़ रुपए मिलना था, जिसमें से 8,915 करोड़ रुपए राज्य को 10 जनवरी, 2025 तक मिल चुका है और ग्रांट्स एंड एड में 13,285 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट और भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए 1,050 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। रेलवे बजट के तहत इस वर्ष 2,700 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए आवंटित किए गए हैं। बिलासपुर के किसानों को आज तक कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा नहीं दिया है और अब सरकार नई भूमि अधिग्रहण भी नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से यह धनराशि राज्य को प्रदान की जा चुकी है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश के लगभग 10 लाख किसानों को लाभ हुआ है। इसी प्रकार 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स छूट का फायदा प्रदेश के करीब 6.5 लाख लोगों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल में अब तक 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और 700 नए बस्तियों को जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी अनेक कार्य हुए हैं, जिनकी सूची बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भाजपा सरकार ने 38,000 पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और ट्रिपल आईटी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिया है। कोल डैम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी प्रदान की है। जब प्राकृतिक आपदा आई थी, तब भारत सरकार ने 1782 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की थी। 10 जुलाई को गृह मंत्रालय ने 180 करोड़ रुपए रिलीज़ किए। 14 जुलाई, 2023 को फिर से हिमाचल प्रदेश के लिए 180 करोड़ रुपए जारी किए गए। 1 अगस्त को 400 करोड़ रुपए जारी किए गए और 7 अगस्त को 189 करोड़ रुपए फिर से रिलीज किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 1,782 करोड़ रुपए जारी किए गए।

श्री नड्डा ने कहा कि अब प्रश्न यह उठता है कि राज्य सरकार ने उस पैसे का वितरण कैसे किया? क्या उसमें बंदरबांट हुई? हिमाचल प्रदेश की यह कांग्रेस सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और कुप्रबंधित सरकारों में से एक है। यह सरकार अपनी नाकामी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेती, बल्कि केंद्र पर आरोप लगाती है। केंद्र के पास ऐसा कौन-सा फंड है जो यहां की कांग्रेस सरकार को नहीं दिया गया? कांग्रेस खुद अपनी नालायकी के कारण सरकार चला नहीं पा रही और दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रही है।

हिमाचल प्रदेश सरकार से जनता दुःखी

श्री नड्डा ने कहा हिमाचल की सुक्खू सरकार एक नॉन-परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है। हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार से दुःखी है और अपने निर्णय पर प्रायश्चित कर रही है। आने वाले समय में वह अपना जवाब भी देगी। ■

इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाएगा: नरेन्द्र मोदी

पहलगाम आतंकी हमला

जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में 22 अप्रैल, 2025 को हमेशा एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। इसी दिन आतंकवादियों ने एक भयावह और कायराना आतंकी घटना को अंजाम देते हुए पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया। हिंसा के इस अमानवीय कृत्य ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित खूबसूरत बैसरन घाटी में हुई।

इस अमानवीय घटना के बाद दशकों में यह पहली बार हुआ कि कश्मीर घाटी सहित पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो गया। समाज के हर कोने से इस हिंसक कृत्य की निंदा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। हमले के बाद भारत और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च और मौन प्रदर्शन हुए, जिसमें इस कृत्य का जमकर विरोध किया गया।

इस आतंकी घटना के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब की अपनी राजकीय यात्रा को बीच में ही स्थगित कर 23 अप्रैल को सुबह-सुबह नई दिल्ली लौट आए। दिल्ली पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर के साथ एक आपात बैठक की।

इसके साथ ही, श्री मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर 23 अप्रैल को 7, लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, "पहलगाम में आतंकवादी हमले के मद्देनजर 7, लोक कल्याण मार्ग पर सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की।"

भारत आतंक के सामने नहीं झुकेगा और इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा: अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आतंकी हमले में प्राण गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 23 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में प्राण गंवाने वालों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, "इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा! उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है तथा यह और भी मजबूत होगा।"

प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मैं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं, उन्हें न्याय के कठघरे में लाया जाएगा... उन्हें बख्शा नहीं जाएगा! उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है तथा यह और भी मजबूत होगा।" ■

इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा, "जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की खबर से बेहद दुःखी हूं। इस कायराना हमले में निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना बेहद निंदनीय है। मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी रख रहे हैं। हम सभी प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हें हरसंभव सहायता प्रदान करेंगे।" ■

आतंक के सामने नहीं झुकेगा और इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री शाह ने पहलगाम आतंकी हमले में प्राण गंवाने वालों के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है, इस दुःख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री शाह ने अस्पताल जाकर आतंकी हमले में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित की

आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को सीमित करने और वर्ष 1960 से लागू सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित कई कदमों की घोषणा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 23 अप्रैल, 2025 को बताया कि भारत पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 से लागू सिंधु जल संधि को 'तत्काल प्रभाव से स्थगित' कर रहा है। यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक के बाद तय की गई पांच-आयामी प्रतिक्रिया का हिस्सा है।

अटारी और सुचेतगढ़ में भारत-पाकिस्तान सीमाएं बंद

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पंजाब के अमृतसर में अटारी-वाघा सीमा को बंद कर दिया। जम्मू के सुचेतगढ़ एवं सांबा में चमलियाल में अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) पर ऑक्ट्रोई पोस्ट पर भी नागरिक आवाजाही को रोका गया, यह कदम पहलगाम हमलों के जवाब में अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) को बंद करने के एक दिन बाद उठाया गया।

कश्मीर में आतंकवादियों के घर ध्वस्त

पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 अप्रैल, 2025 को कश्मीर के विभिन्न जिलों में चार आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। पुलवामा, शोपियां, कुपवाड़ा और कुलगाम जिलों में सक्रिय आतंकवादियों से जुड़ी संपत्तियों पर यह कार्रवाई की गई।

निर्दोष नागरिकों पर नृशंस हमला कायरतापूर्ण कृत्य है: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, "पहलगाम (जम्मू और कश्मीर) में आतंकवादी हमले की खबर से बहुत दुःखी हूं। निर्दोष नागरिकों पर यह नृशंस हमला कायरतापूर्ण और अत्यंत निंदनीय है। मेरी संवेदनाएं उन निर्दोष पीड़ितों एवं उनके परिवारों के साथ हैं।"

मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से दुःखी हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। इस कायराना आतंकी घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को घटना की जानकारी दी गई है तथा संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। सभी एजेंसियों के साथ तत्काल सुरक्षा समीक्षा बैठक करने के लिए जल्द ही श्रीनगर जा रहा हूं।"

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले छह साल में सबसे निचले स्तर पर

2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.6 प्रतिशत हुई, सालाना आधार पर मार्च में 3.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापा जाता है और यह रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं की लागत को दर्शाता है। खुदरा मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय रूप से 4.6 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई, जो 2018-19 के बाद से सबसे कम है। उल्लेखनीय रूप से मार्च, 2025 के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति दर 3.34 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई, जो फरवरी, 2025 से 27 आधार अंक कम है। यह अगस्त, 2019 के बाद से सबसे कम मासिक मुद्रास्फीति दर है। ये आंकड़े आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मूल्य वृद्धि को रोकने के निरंतर प्रयास को दर्शाते हैं।

इन परिणामों को प्राप्त करने में सरकार के रणनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण रहे हैं। मुख्य उपायों में आवश्यक खाद्य पदार्थों के बफर स्टॉक को मजबूत करना और उन्हें समय-समय पर खुले बाजारों में जारी करना, साथ ही चावल, गेहूं का आटा, दालें और प्याज जैसी मंडी की सब्सिडी वाली खुदरा बिक्री शामिल है। महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों पर सरलीकृत आयात शुल्क, जमाखोरी को रोकने के लिए सख्त स्टॉक सीमा और आवश्यक वस्तुओं पर कम जीएसटी दरों ने कीमतों के दबाव को और कम कर दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सहायता और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी लक्षित सब्सिडी ने कमजोर परिवारों को बढ़ती खाद्यान्न लागत से बचाया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कम मुद्रास्फीति का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है?

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) समय के साथ खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों में से एक है। यह दर्शाता है कि परिवारों को भोजन, कपड़े, आवास और ईंधन जैसी वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा पर कितना खर्च करने की आवश्यकता है। भारत में सीपीआई को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है और वर्तमान में आधार वर्ष 2012 का उपयोग करके इसकी गणना की जाती है। समय के साथ इस निश्चित मात्रा की लागत को ट्रैक करके सीपीआई दिखाता है कि कीमतें कैसे बढ़ती या घटती हैं, जो उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति और उनके समग्र कल्याण को प्रभावित करती हैं।

सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं की इस निश्चित मात्रा की वर्तमान लागत की तुलना पिछली अवधि में इसकी लागत से करके मूल्य परिवर्तनों को मापता है। चूंकि इस सामग्री को मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में स्थिर रखा जाता है, इसलिए सूचकांक में कोई भी परिवर्तन केवल कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो सीपीआई बढ़ जाती है, जो मुद्रास्फीति का संकेत देती है; जब वे गिरती हैं, तो सीपीआई घट जाती है, जो कम मुद्रास्फीति या अपस्फीति का संकेत देती है।

मूल रूप से सीपीआई के आंकड़े श्रमिकों के जीवन-यापन की लागत में परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए विकसित किए गए थे ताकि उनकी मजदूरी को मूल्य उतार-चढ़ाव के अनुरूप समायोजित किया जा सके। हालांकि, समय के साथ सीपीआई एक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले मैक्रो-इकॉनॉमिक टूल के रूप में विकसित हुआ है। यह अब मुद्रास्फीति को लक्षित करने, मूल्य स्थिरता की निगरानी करने और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रमुख मानक है। यह वास्तविक आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय खातों में एक अपस्फीतिकारक के रूप में भी कार्य करता है।

भारत में सामान्य सीपीआई (सीपीआई-संयुक्त) के साथ-साथ विभिन्न जनसंख्या समूहों को ध्यान में रखते हुए खंड-विशिष्ट सूचकांक भी प्रकाशित किए जाते हैं:

- सीपीआई (आईडब्ल्यू) — औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- सीपीआई (एएल) — कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
- सीपीआई (आरएल) — ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

ये सूचकांक मजदूरी संशोधन, ग्रामीण नियोजन और जनसंख्या के विशिष्ट क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के रुझान को समझने में मदद करते हैं।

मार्च, 2025 के लिए मुख्य बिंदु

खाद्य मुद्रास्फीतिः उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित साल-दर-साल खाद्य मुद्रास्फीति मार्च, 2025 में 2.69 प्रतिशत रही, जो नवंबर, 2021 के बाद सबसे कम है। यह पिछले महीने से 106 आधार अंकों की तीव्र गिरावट को दर्शाता है।

ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीतिः 2.82 प्रतिशत

शहरी खाद्य मुद्रास्फीतिः 2.48 प्रतिशत

गिरावट के कारकः खाद्य कीमतों में समग्र कमी का कारण सब्ज़ियां, अंडे, दालें और उत्पाद, मांस और मछली, अनाज और उत्पाद, दूध और उत्पाद जैसी प्रमुख श्रेणियों में महंगाई में गिरावट रही।

ग्रामीण मुद्रास्फीतिः ग्रामीण क्षेत्रों में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई।

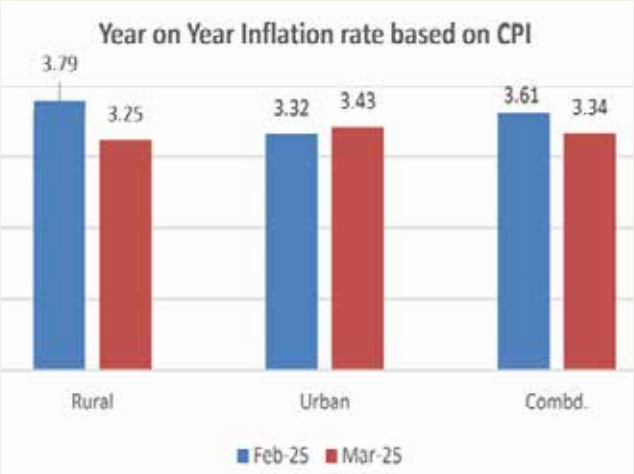

फरवरी में हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.79 प्रतिशत से गिरकर मार्च में 3.25 प्रतिशत हो गई।

खाद्य मुद्रास्फीति 4.06 प्रतिशत से गिरकर 2.82 प्रतिशत हो गई।

शहरी मुद्रास्फीति: शहरी क्षेत्रों में हेडलाइन मुद्रास्फीति फरवरी में 3.32 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 3.43 प्रतिशत हो गई। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति 3.15 प्रतिशत से घटकर 2.48 प्रतिशत हो गई।

आवास मुद्रास्फीति: शहरी क्षेत्र के लिए आवास मुद्रास्फीति फरवरी में 2.91 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर मार्च, 2025 में 3.03 प्रतिशत हो गई।

ईंधन और बिजली: इस श्रेणी में मुद्रास्फीति फरवरी में -1.33 प्रतिशत से बढ़कर मार्च में 1.48 प्रतिशत हो गई, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं।

शिक्षा मुद्रास्फीति: शिक्षा से सम्बंधित मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि देखी गई, जो पिछले महीने के 3.83 प्रतिशत से बढ़कर 3.98 प्रतिशत हो गई।

स्वास्थ्य मुद्रास्फीति: स्वास्थ्य खंड में कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई, मार्च में मुद्रास्फीति 4.26 प्रतिशत रही, जबकि फरवरी में यह 4.12 प्रतिशत थी।

परिवहन और संचार: इस श्रेणी में मुद्रास्फीति फरवरी में 2.93 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2025 में बढ़कर 3.30 प्रतिशत हो गई।

सबसे अधिक मुद्रास्फीति वाली वस्तुएं: मार्च, 2025 में सबसे अधिक साल-दर-साल मुद्रास्फीति वाली शीर्ष पांच वस्तुएं नारियल तेल (56.81 प्रतिशत), नारियल (42.05 प्रतिशत), सोना (34.09 प्रतिशत), चांदी (31.57 प्रतिशत) और अंगूर (25.55 प्रतिशत) थीं।

सबसे कम मुद्रास्फीति वाली वस्तुएं: कीमतों में सबसे अधिक गिरावट वाली वस्तुएं अदरक (-38.11 प्रतिशत), टमाटर (-34.96 प्रतिशत), फूलगोभी (-25.99 प्रतिशत), जीरा (-25.86 प्रतिशत) और लहसुन (-25.22 प्रतिशत) रही।

खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार तीसरे साल कमी आई

भारत में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले तीन वित्तीय वर्षों में लगातार नीचे की ओर चलायमान रही है, जो 2022-23 में 6.7 प्रतिशत से गिरकर 2023-24 में 5.4 प्रतिशत और 2024-25 में 4.6 प्रतिशत हो गई है। यह निरंतर कमी भारतीय रिजर्व बैंक की संतुलित मौद्रिक नीति और भारत सरकार द्वारा आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को कम करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के लिए किए गए केंद्रित हस्तक्षेपों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। गिरावट की प्रवृत्ति ने जीवन-यापन की लागत के दबाव को कम करने और आर्थिक विकास के लिए अधिक स्थिर वातावरण को बढ़ावा देने में मदद की है।

उच्च कीमतों से स्थिरता तक: मुद्रास्फीति नियंत्रण का एक दशक

2009-10 और 2013-14 के बीच भारत ने उच्च मुद्रास्फीति का एक लंबी अवधि का सामना किया, जिसमें औसत वार्षिक दर दोहरे अंकों में रही। देश भर के परिवारों ने खाद्य और ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि का खामियाजा भुगता, इन वजह से क्रय शक्ति में कमी आ गई थी और उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बन गया था। व्यापक समय सीमा पर देखें तो 2004-05 और 2013-14 के बीच औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2 प्रतिशत रही, जिससे पता चलता है कि यह एक खुदरा कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव वाला दशक था।

इसके विपरीत 2015-16 से 2024-25 तक की दस साल की अवधि में मुद्रास्फीति के दबाव में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिसमें औसत दर 5 प्रतिशत तक कम हो गई। यह महत्वपूर्ण कमी बेहतर आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन, राजकोषीय विवेक और मुद्रास्फीति-लक्ष्यित मौद्रिक नीति के माध्यम से मूल्य स्थिरता में सुधार करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। उच्च मुद्रास्फीति के दौर से अधिक स्थिर मूल्य निर्धारण वातावरण में बदलाव ने उपभोक्ताओं के लिए अधिक निश्चितता प्रदान की है और दीर्घकालिक आर्थिक विकास की नींव को मजबूत किया है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में हाल के वर्षों में खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत सरकार द्वारा समन्वित प्रयासों की सफलता है। सक्रिय मौद्रिक नीतियों से लेकर लक्षित राजकोषीय उपायों तक, दृष्टिकोण समावेशी और प्रभावी दोनों रहा है। यह उपभोक्ताओं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मूल्य उतार-चढ़ाव से होने वाली अस्थिरता से बचाते हैं। 2018-19 के बाद से अब तक मुद्रास्फीति अपने सबसे निचले स्तर पर है, भारत ने न केवल व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत किया है, बल्कि सतत विकास के लिए एक सक्षम वातावरण भी बनाया है। यह प्रक्षेप पथ विकास लक्ष्यों से समझौता किए बिना देश में लचीलेपन और प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है। ■

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल निर्यात 5.50 प्रतिशत बढ़कर 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान

इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 32.47 प्रतिशत बढ़कर 38.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में 29.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 16 अप्रैल को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारत का कुल निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 5.50 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के दौरान कुल आयात 915.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान है, जो 6.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यहां प्रस्तुत है इस विज्ञप्ति की प्रमुख बातें:

- वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के दौरान व्यापारिक निर्यात का संचयी मूल्य 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 437.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.08 प्रतिशत ज्यादा है
- वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में संचयी गैर-पेट्रोलियम निर्यात का मूल्य 374.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 352.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 6.0 प्रतिशत ज्यादा है
- वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में व्यापारिक निर्यात वृद्धि के प्रमुख चालकों में कॉफ़ी, तम्बाकू, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, जूट निर्माण जिसमें फ़्लोर कवरिंग, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, चाय, कालीन, प्लास्टिक और लिनोलियम, सभी वस्त्रों का आरएमजी, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य वस्तुएं और विविध प्रसंस्कृत वस्तुएं, माइका, कोयला और अन्य अयस्क, प्रसंस्कृत खनिजों सहित खनिज, इंजीनियरिंग सामान और फल और सब्जियां शामिल हैं
- इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 32.47 प्रतिशत बढ़कर 38.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में 29.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था
- चावल का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 19.73 प्रतिशत बढ़कर 12.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में 10.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर था
- सभी वस्त्र निर्यात का आरएमजी वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 10.03 प्रतिशत बढ़कर 15.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में 14.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था
- दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 9.39 प्रतिशत बढ़कर 30.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में 27.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर था
- इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) में 6.74 प्रतिशत बढ़कर 116.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-मार्च) में 109.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था ■

सुखोई-30 एमकेआई विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम 'गौरव' का सफल परीक्षण

परीक्षण के बाद 1,000 किलोग्राम वजनी इस ग्लाइड बम को भारतीय वायुसेना में शामिल किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 8-10 अप्रैल, 2025 के बीच सुखोई-30 एमकेआई युद्धक विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम (एलआरजीबी) 'गौरव' का सफल परीक्षण किया। परीक्षणों के दौरान हथियार को द्वीप पर जमीनी लक्ष्य के साथ विभिन्न वारहेड कॉन्फ़िगरेशन में कई स्टेशनों से एकीकृत किया गया, जो लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सफल रहा।

लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम 'गौरव' 1,000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला 'रिसर्च सेंटर इमारत' (आरसीआई), आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन परीक्षणों में भाग लिया और इसकी समीक्षा की।

इस प्रणाली को विकास-सह-उत्पादन भागीदारों - अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज और विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सहयोग से साकार रूप दिया गया। परीक्षण के बाद इस ग्लाइड बम को भारतीय वायुसेना में शामिल किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सैन्य उड़ान योग्यता एवं प्रमाणन केंद्र तथा वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय ने प्रमाणन और गुणवत्ता में योगदान दिया।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 'गौरव' के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और उद्योग जगत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम विकसित होने से सशस्त्र बलों की क्षमताएं और बढ़ेंगी। ■

स्वतंत्र भारत में पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पार

पिछले 11 वर्षों में उत्पादन में 347% के उछाल के साथ चार गुना और बिक्री में 447% की बढ़ोतरी के साथ पांच गुना की वृद्धि हुई; 11 वर्षों में कुल रोजगार सृजन के क्षेत्र में 49.23% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी, 1.94 करोड़ लोगों को केवीआईसी दे रहा रोजगार

देश में आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त करने वाले खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र ने बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के मार्गदर्शन में न केवल नई ऊंचाइयों को छुआ है, बल्कि करोड़ों ग्रामीणों के जीवन में भी नयी रोशनी का संचार किया है।

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) ने वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री और नये रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447 प्रतिशत, उत्पादन में 347 प्रतिशत और रोजगार सृजन में 49.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में वर्ष 2013-14 की तुलना में बिक्री में 399.69% और उत्पादन में 314.79% की वृद्धि दर्ज की गयी थी।

वित्त वर्ष 2013-14 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन जहां 26109.07 करोड़ रुपये था, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह करीब चार गुना बढ़कर 347 प्रतिशत के उछाल के साथ 116599.75 करोड़ रुपये पहुंच गया। जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में बिक्री जहां 31154.19 करोड़ रुपये थी, वहीं करीब पांच गुना बढ़कर 447 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि के साथ यह वित्त वर्ष 2024-25 में 170551.37 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो कि अब तक की सर्वाधिक बिक्री है।

पिछले 11 वर्षों में खादी कपड़ों के उत्पादन में भी अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां खादी कपड़ों का उत्पादन 811.08 करोड़ रुपये था, वहीं 366 प्रतिशत उछाल के साथ यह साढ़े चार गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में यह 3783.36 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंच गया, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

खादी कपड़ों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां इसकी बिक्री सिर्फ 1081.04 करोड़ रुपये थी, वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में 561 प्रतिशत वृद्धि के साथ यह करीब साढ़े छह गुना बढ़कर 7145.61 करोड़ रुपये पहुंच गई। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बड़े मंच से खादी का प्रचार करने का व्यापक असर खादी के कपड़ों की बिक्री पर पड़ा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करना है। इस क्षेत्र में भी केवीआईसी ने पिछले 11 वर्षों में रिकॉर्ड कायम किया है। वित्त वर्ष 2013-14 में जहां संचयी रोजगार (Cumulative Employment) 1.30 करोड़ था, वहीं यह 2024-25 में 49.23 प्रतिशत वृद्धि के साथ 1.94 करोड़ तक पहुंच गया। ■

ईपीएफओ ने फरवरी, 2025 में 16.10 लाख सदस्य जोड़े

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने फरवरी, 2025 के लिए पेरोल डेटा जारी किया है, जिसमें 16.10 लाख सदस्यों की वृद्धि हुई है। साल-दर-साल विश्लेषण से पता चलता है कि फरवरी, 2024 की तुलना में पेरोल वृद्धि में 3.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरुकता को दर्शाता है, जिसे ईपीएफओ की प्रभावी आउटरीच पहलों से बल मिला है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल को जारी एक बयान के अनुसार ईपीएफओ ने फरवरी, 2025 में लगभग 7.39 लाख नए ग्राहक जोड़े। नए ग्राहकों की यह संख्या रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरुकता और ईपीएफओ के सफल आउटरीच कार्यक्रमों के भरोसे संभव हुई है।

आंकड़ों का एक उल्लेखनीय पहलू 18-25 आयु वर्ग का प्रभुत्व है। इस 18-25 आयु वर्ग में 4.27 लाख नए ग्राहक जुड़े, जो फरवरी, 2025 में जोड़े गए कुल नए ग्राहकों का महत्वपूर्ण 57.71 प्रतिशत है। यह पहले जैसा है जो दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं, मुख्य रूप से पहली बार नौकरी चाहने वाले।

फरवरी, 2025 में लगभग 2.08 लाख नई महिला ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुईं। यह फरवरी, 2024 की तुलना में 1.26 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा महीने के दौरान कुल महिला पेरोल वृद्धि लगभग 3.37 लाख रही, जो फरवरी, 2024 की तुलना में 9.23 प्रतिशत की महत्वपूर्ण साल-दर-साल वृद्धि है। महिला सदस्यों में वृद्धि अधिक समावेशी और विविध कार्यबल की ओर बड़े बदलाव का संकेत है। ■

'नेशनल हेराल्ड का मामला धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है'

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 17 अप्रैल, 2025 को केन्द्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं की संलिप्तता पर बड़े खुलासे किए। श्री पुरी ने बताया कि दिल्ली के बहादुरशाह जफर मार्ग पर स्थित प्लॉट नंबर 5A की बिल्डिंग में नेशनल हेराल्ड की कभी प्रेस चल ही नहीं रही थी, जबकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा प्रेस चलाने के लिए ही बहुत ही कम दर पर भूमि उपलब्ध करायी गयी थी। कांग्रेस नेताओं ने इन बिल्डिंग्स का निजी और व्यवसायिक उपयोग किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित पूरे देश को धोखा दिया।

श्री पुरी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा यह केस फाइल किए जाने पर कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा का कांग्रेस से बस इतना कहना है कि वह थोड़ा आत्ममंथन करें। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रही है, असल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। नेशनल हेराल्ड का इतिहास बहुत पुराना है, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था। हालांकि, 2008 में इस अखबार की छपाई बंद हो गई थी और इसके बाद नेशनल हेराल्ड केस 2012-13 के आसपास शुरू हुआ। इस मामले में भाजपा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। असली प्रश्न यह है कि कैसे महज 50 लाख रुपये की रकम से 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की गई?

उन्होंने कहा कि यह नेशनल हेराल्ड का मामला धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और पूरी तरह से शट एंड क्लोज केस हैं। 2014 में जब यह मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आया था, उस समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'यह प्रतीत होता है कि यंग इंडिया लिमिटेड (वाईआईएल) को सार्वजनिक धन को निजी उपयोग में बदलने के उद्देश्य के साथ बनाया गया।' यह मामला 2014 से लगातार विभिन्न अदालतों में घूमता रहा है और कांग्रेस पार्टी ने अपने वकीलों का उपयोग करके इसे कई बार टालने का प्रयास किया है। यंग इंडिया लिमिटेड को 2010 में एक सेक्शन 25 के तहत कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था, जिसका उद्देश्य चैरिटी था और इसकी पूंजी 5 लाख रुपये थी। इसके बावजूद, कांग्रेस पार्टी ने यह लोन बढ़ाकर 80-90 करोड़ रुपए तक कर दिया और अब सवाल यह उठता है कि इसे चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कदम उठाए हैं? इसके बाद, 50 लाख रुपये की राशि प्राप्त कर 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की गई। ■

प्रमुख बिंदु

- कांग्रेस की वास्तविक रुचि अखबार प्रकाशित करने में नहीं थी, यह परिवार पहले से ही एजेएल की संपत्तियों को लेकर 'रियल एस्टेट' में सक्रिय था।
- बहादुरशाह जफर मार्ग पर स्थित प्लॉट नंबर 5A को 1963 में एजेएल को 1.25 लाख प्रति एकड़ की दर से अलॉट किया गया था, जिसमें प्रेस और ऑफिस होना प्रस्तावित था, लेकिन 2016 में जांच में पता चला कि इस बिल्डिंग में कभी प्रिंटिंग प्रेस थी ही नहीं।
- इस बिल्डिंग में बेसमेंट पूरी तरह से खाली था, जबकि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर पासपोर्ट ऑफिस किराए पर दिया गया था जबकि सेकंड और थर्ड फ्लोर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को किराए पर दिया गया था, जिससे बड़ी रकम में किराया प्राप्त हुआ।
- नवंबर 2010 में, गांधी परिवार ने एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम था 'यंग इंडिया' और 90 करोड़ के बकाया लोन को भरने के लिए केवल 50 लाख का भुगतान किया।
- केवल 50 लाख में एजेएल के 99% शेयर यंग इंडिया को ट्रांसफर किए गए, जबकि एजेएल की संपत्तियों की कीमत 2000 करोड़ से अधिक थी। कुछ लोग तो यह दावा करते हैं कि इनकी वास्तविक कीमत 5000 करोड़ के करीब है।
- 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार की छपाई बंद हो गई थी और 2012-13 में यह मामला शुरू हुआ। इस मामले में भाजपा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था।
- 2014 में जब यह मामला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष आया तो उस समय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि 'यह प्रतीत होता है कि यंग इंडिया लिमिटेड सार्वजनिक धन को निजी उपयोग में बदलने के उद्देश्य के साथ बनाया गया।'
- कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, जिन्होंने चैरिटेबल उद्देश्य का गलत इस्तेमाल किया और पार्टी के संसाधनों को निजी लाभ के लिए उपयोग किया।
- 2008 में अखबार के बंद होने पर खड़गे सहित बाकी कांग्रेस नेता क्या कर रहे थे? कृपया एक सूची दें कि उस समय कांग्रेस ने उस अखबार को चलाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए? ■

स्टैंड-अप इंडिया के 9 वर्ष
समावेशी विकास को प्रोत्साहन

5 अप्रैल, 2016 को अपने आरंभ के बाद से स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य पर है। इसका उद्देश्य नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बैंक लोन प्रदान करके बाधाओं को तोड़ना है। बीते 9 वर्षों में इस योजना ने न केवल व्यवसायों को वित्त पोषित किया है, बल्कि इसने सपनों को पोषित किया है, आजीविका का सृजन किया है और पूरे भारत में समावेशी विकास को आगे बढ़ाया है।

स्टैंड-अप इंडिया के अंतर्गत उपलब्धियां

स्टैंड-अप इंडिया योजना ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दिखाई है, जिसकी शुरुआत के बाद से स्वीकृत कुल राशि 31 मार्च, 2019 तक 16,085.07 करोड़ रुपये से बढ़कर 17 मार्च, 2025 तक 61,020.41 करोड़ रुपये हो गई। यह एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो देश भर में उद्यमियों को सशक्त बनाने में योजना के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

इस योजना ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों और महिला उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सशक्तीकरण को प्रतिबिंबित किया (मार्च, 2018 से मार्च, 2024 तक):

- अनुसूचित जाति के खाते बढ़कर 9,399 से 46,248 हो गए, तथा लोन की राशि बढ़कर 1,826.21 करोड़ रुपये से 9,747.11 करोड़ रुपये हो गई।
- अनुसूचित जनजाति के खाते बढ़कर 2,841 से 15,228 हो गए तथा स्वीकृत लोन की राशि बढ़कर 574.65 करोड़ रुपये से 3,244.07 करोड़ रुपये हो गई।
- 2018 से 2024 तक महिला उद्यमियों के खाते बढ़कर 55,644 से 1,90,844 हो गए तथा स्वीकृत राशि बढ़कर 12,452.37 करोड़ रुपये से 43,984.10 करोड़ रुपये हो गई।

निष्कर्ष

स्टैंड-अप इंडिया योजना एक बदलावकारी पहल रही है, जिसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को अपने व्यावसायिक विचारों को हकीकत में बदलने के लिए सशक्त बनाया है। लोन स्वीकृति और वितरण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ यह समावेशी विकास को प्रोत्साहन देना जारी रखता है। यह योजना केवल लोन के बारे में नहीं है; यह अवसर पैदा करने, बदलाव को प्रेरित करने और आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने के बारे में है। ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

वाल्मीकि प्रसाद सिंह

श्री वाल्मीकि प्रसाद सिंह भारतीय जनसंघ में जिला मंत्री रहे। उन्होंने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1971 में उन्होंने जनसंघ के टिकट पर समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा। आपातकाल के दौरान श्री वाल्मीकि प्रसाद को डीआईआर एक्ट (डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट) के तहत गिरफ्तार कर आठ महीने जेल में रखा गया। ■

मेरे अटल जी

नरेन्द्र मोदी

अटल जी अब नहीं रहे। मन नहीं मानता। अटल जी, मेरी आंखों के सामने हैं, स्थिर हैं। जो हाथ मेरी पीठ पर धौल जमाते थे, जो स्नेह से, मुस्कराते हुए मुझे अंकवार में भर लेते थे, वे स्थिर हैं। अटल जी की ये स्थिरता मुझे झकझोर रही है, अस्थिर कर रही है। एक जलन सी है आंखों में, कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा। मैं खुद को बार-बार यकीन दिला रहा हूं कि अटल जी अब नहीं हैं, लेकिन ये विचार आते ही खुद को इस विचार से दूर कर रहा हूं। क्या अटल जी वाकई नहीं हैं? नहीं। मैं उनकी आवाज अपने भीतर गूंजते हुए महसूस कर रहा हूं, कैसे कह दूं, कैसे मान लूं, वे अब नहीं हैं।

वे पंचतत्व हैं। वे आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सबमें व्याप्त हैं, वे अटल हैं, वे अब भी हैं। जब उनसे पहली बार मिला था, उसकी स्मृति ऐसी है जैसे कल की ही बात हो। इतने बड़े नेता, इतने बड़े विद्वान। लगता था जैसे शीशे के उस पार की दुनिया से निकलकर कोई सामने आ गया है।

जिसका इतना नाम सुना था, जिसको इतना पढ़ा था, जिससे बिना मिले, इतना कुछ सीखा था, वो मेरे सामने थे। जब पहली बार उनके मुंह से मेरा नाम निकला तो लगा, पाने के लिए बस इतना ही बहुत है। बहुत दिनों तक मेरा नाम लेती हुई उनकी वह आवाज मेरे कानों से टकराती रही। मैं कैसे मान लूं कि वह आवाज अब चली गई है।

कभी सोचा नहीं था, कि अटल जी के बारे में ऐसा लिखने के लिए कलम उठानी पड़ेगी। देश और दुनिया अटल जी को एक स्टेट्समैन, धारा प्रवाह वक्ता, संवेदनशील कवि, विचारवान लेखक, धारदार पत्रकार और विजनरी जननेता के तौर पर जानती है, लेकिन मेरे लिए उनका स्थान इससे भी ऊपर का था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उनके साथ बरसों तक काम करने का अवसर मिला, बल्कि मेरे जीवन, मेरी सोच, मेरे आदर्शों-मूल्यों पर जो छाप उन्होंने छोड़ी, जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया, उसने मुझे गढ़ा है, हर स्थिति में अटल रहना सिखाया है।

हमारे देश में अनेक ऋषि, मुनि, संत आत्माओं ने जन्म लिया है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक की विकास यात्रा के लिए भी असंख्य लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त, सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व है।

> **स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र की रक्षा और 21वीं सदी के सशक्त, सुरक्षित भारत के लिए अटल जी ने जो किया, वह अभूतपूर्व है**

उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था – बाकी सब का कोई महत्त्व नहीं। इंडिया फर्स्ट – भारत प्रथम, ये मंत्र वाक्य उनका जीवन ध्येय था। पोखरण देश के लिए जरूरी था तो चिंता नहीं की प्रतिबंधों और आलोचनाओं की, क्योंकि देश प्रथम था। सुपर कंप्यूटर नहीं मिले, क्रायोजेनिक इंजन नहीं मिले तो परवाह नहीं, हम खुद बनाएंगे, हम खुद अपने दम पर अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक कुशलता के बल पर असंभव दिखने वाले कार्य संभव कर दिखाएंगे और ऐसा किया भी। दुनिया को चकित किया। सिर्फ एक ताकत उनके भीतर काम करती थी— देश प्रथम की जिद।

काल के कपाल पर लिखने और मिटाने की ताकत, हिम्मत और चुनौतियों के बादलों में विजय का सूरज उगाने का चमत्कार उनके सीने में था, तो इसलिए क्योंकि वह सीना देश प्रथम के लिए धड़कता था। इसलिए हार और जीत उनके मन पर असर नहीं करती थी। सरकार बनी तो भी, सरकार एक वोट से गिरा दी गयी तो भी, उनके स्वरों में पराजय को भी विजय के ऐसे गगनभेदी विश्वास में बदलने की ताकत थी कि जीतने वाला ही हार मान बैठे।

अटल जी कभी लीक पर नहीं चले। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नए रास्ते बनाए और तय किए। 'आंधियों में भी दीये जलाने' की क्षमता उनमें थी। पूरी बेबाकी से वे जो कुछ भी बोलते थे, सीधा जनमानस के हृदय में उतर जाता था। अपनी बात को कैसे रखना है, कितना कहना है और कितना अनकहा छोड़ देना है, इसमें उन्हें महारत हासिल थी।

राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की, विश्व में मां भारती के मान-सम्मान को उन्होंने जो बुलंदी दी, इसके लिए उन्हें अनेक सम्मान भी मिले। देशवासियों ने उन्हें 'भारत रत्न' देकर अपना मान भी बढ़ाया। लेकिन वे किसी भी विशेषण, किसी भी सम्मान से ऊपर थे।

जीवन कैसे जीया जाए, राष्ट्र के काम कैसे आया जाए, यह उन्होंने अपने जीवन से दूसरों को सिखाया। वे कहते थे, "हम केवल अपने लिए ना जीएं, औरों के लिए भी जीएं... हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी"

देश के गरीब, वंचित, शोषित के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए वे जीवन भर

प्रयास करते रहे। वे कहते थे "गरीबी, दरिद्रता गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि यह विवशता है, मजबूरी है और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता।" करोड़ों देशवासियों को इस विवशता से बाहर निकालने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किए। गरीब को अधिकार दिलाने के लिए देश में आधार जैसी व्यवस्था, प्रक्रियाओं का ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण, हर गांव तक सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज, देश में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्र निर्माण के उनके संकल्पों से जुड़ा था।

आज भारत जिस टेक्नोलॉजी के शिखर पर खड़ा है उसकी आधारशिला अटल जी ने ही रखी थी। वे अपने समय से बहुत दूर तक देख सकते थे — स्वप्नद्रष्टा थे लेकिन कर्मवीर भी थे। कवि हृदय, भावुक मन के थे तो पराक्रमी सैनिक मन वाले भी थे। उन्होंने विदेश की यात्राएं कीं। जहां-जहां भी गए, स्थायी मित्र बनाये और भारत के हितों की स्थायी आधारशिला रखते गए। वे भारत की विजय और विकास के स्वर थे।

अटल जी का प्रखर राष्ट्रवाद और राष्ट्र के लिए समर्पण करोड़ों देशवासियों को हमेशा से प्रेरित करता रहा है। राष्ट्रवाद उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि जीवन शैली थी। वे देश को सिर्फ एक भूखंड, ज़मीन का टुकड़ा भर नहीं मानते थे, बल्कि एक जीवंत, संवेदनशील इकाई के रूप में देखते थे। "भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्रपुरुष है।" यह सिर्फ भाव नहीं, बल्कि उनका संकल्प था, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दशकों का सार्वजनिक जीवन उन्होंने अपनी इसी सोच को जीने में, धरातल पर उतारने में लगा दिया। आपातकाल ने हमारे लोकतंत्र पर जो दाग लगाया था उसको मिटाने के लिए अटल जी के प्रयास को देश हमेशा याद रखेगा।

देश के गरीब, वंचित, शोषित के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अटल जी जीवन भर प्रयास करते रहे। वे कहते थे "गरीबी, दरिद्रता गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि यह विवशता है, मजबूरी है और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता।"

राष्ट्रभक्ति की भावना, जनसेवा की प्रेरणा उनके नाम के ही अनुकूल अटल रही। भारत उनके मन में रहा, भारतीयता तन में। उन्होंने देश की जनता को ही अपना आराध्य माना। भारत के कण-कण, कंकर-कंकर, भारत की बूंद-बूंद को, पवित्र और पूजनीय माना।

जितना सम्मान, जितनी ऊंचाई अटल जी को मिली उतना ही अधिक वह ज़मीन से जुड़ते गए। अपनी सफलता को कभी भी उन्होंने अपने मस्तिष्क पर प्रभावी नहीं होने दिया। प्रभु से यश, कीर्ति की कामना अनेक व्यक्ति करते हैं, लेकिन ये अटल जी ही थे जिन्होंने कहा,

"हे प्रभु! मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना।
गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना"

अपने देशवासियों से इतनी सहजता और सरलता से जुड़े रहने की यह कामना ही उनको सामाजिक जीवन के एक अलग पायदान पर खड़ा करती है।

वे पीड़ा सहते थे, वेदना को चुपचाप अपने भीतर समाये रहते थे, पर सबको अमृत देते रहे- जीवन भर। जब उन्हें कष्ट हुआ तो कहने लगे— "देह धरण को दंड है, सब काहू को होये, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूरख भुगते रोए।" उन्होंने ज्ञान मार्ग से अत्यंत गहरी वेदनाएं भी सहन कीं और वीतरागी भाव से विदा ले गए।

यदि भारत उनके रोम-रोम में था तो विश्व की वेदना उनके मर्म को भेदती थी। इसी वजह से हिरोशिमा जैसी कविताओं का जन्म हुआ। वे विश्व नायक थे। 'मां भारती' के सच्चे वैश्विक नायक। भारत की सीमाओं के परे भारत की कीर्ति और करुणा का संदेश स्थापित करने वाले आधुनिक बुद्ध।

कुछ वर्ष पहले लोकसभा में जब उन्हें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ सांसद के सम्मान से सम्मानित किया गया था तब उन्होंने कहा था, "यह देश बड़ा अद्भुत है, अनूठा है। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा सकता है।"

अपने पुरुषार्थ को, अपनी कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्र के लिए समर्पित करना उनके व्यक्तित्व की महानता को प्रतिबिंबित करता है। यही सवा सौ करोड़ देशवासियों के लिए उनका सबसे बड़ा और प्रखर संदेश है। देश के साधनों, संसाधनों पर पूरा भरोसा करते हुए, हमें अब अटल जी के सपनों को पूरा करना है, उनके सपनों का भारत बनाना है।

नए भारत का यही संकल्प, यही भाव लिए मैं अपनी तरफ से और सवा सौ करोड़ देशवासियों की तरफ से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

प्रधानमंत्री की सऊदी अरब यात्रा

भारत-सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंध रणनीतिक साझेदारी से और मजबूत हुए

क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब साम्राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अप्रैल, 2025 को सऊदी अरब साम्राज्य की राजकीय यात्रा की। यह श्री मोदी की सऊदी अरब साम्राज्य की तीसरी यात्रा थी। यह एचआरएच प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब साम्राज्य के प्रधानमंत्री की सितंबर, 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने और भारत-सऊदी अरब सामरिक साझेदारी परिषद् की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता करने की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के बाद हुई है।

महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री ने अल-सलाम पैलेस, जेद्दा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की। भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंध हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जो विश्वास और सद्भावना से भरे हैं।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत

दोनों पक्षों ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की ठोस नींव रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित विविध क्षेत्रों को कवर करने वाली रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से और मजबूत हुई है। दोनों पक्षों ने आपसी हितों के मौजूदा क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों नेताओं ने भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर रचनात्मक चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद् (एसपीसी) की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता भी की।

दोनों नेताओं ने विभिन्न मंत्रालयों की बड़ी संख्या में उच्च-स्तरीय यात्राओं की सराहना की, जिससे दोनों पक्षों में विश्वास और आपसी समझ बढ़ी है। बैठक के अंत में दोनों नेताओं ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद् की दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर किए।

भारतीय पक्ष ने सऊदी अरब में रहने वाले लगभग 2.7 मिलियन भारतीय नागरिकों के निरंतर कल्याण के लिए सऊदी पक्ष की सराहना की, जो दोनों देशों के बीच मौजूद लोगों के बीच मजबूत संबंधों और अपार सद्भावना को दर्शाता है।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 2024 में गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स (एचएलटीएफ) के तहत चर्चाओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, फिनटेक, डिजिटल बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्माण और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में भारत में निवेश करने के सऊदी अरब के प्रयास पर यह नोट किया गया कि उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ने कई क्षेत्रों में समझ बनाई है जो इस तरह के निवेश प्रवाह को तेजी से बढ़ावा देगी।

ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय पक्ष ने वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता बढ़ाने और वैश्विक ऊर्जा बाजार की गतिशीलता को संतुलित करने के लिए सऊदी अरब के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने वैश्विक बाजारों में सभी ऊर्जा स्रोतों के लिए आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों पक्षों ने हरित/स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर जोर दिया, जिसमें मांग को प्रोत्साहित करना, हाइड्रोजन परिवहन और भंडारण प्रौद्योगिकियों का विकास करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान-प्रदान करना शामिल है।

सऊदी अरब साम्राज्य ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, एक सूर्य-एक विश्व-एक ग्रिड, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल (एलआईएफई) और वैश्विक हरित ऋण पहल जैसी अग्रणी पहलों के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई में भारत के योगदान की सराहना की।

दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि

परिणामों की सूची

रणनीतिक साझेदारी परिषद्

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद् (एसपीसी) की नेताओं की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री महामहिम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 22 अप्रैल, 2025 को जेद्दा में की। परिषद् ने एसपीसी के तहत विभिन्न समितियों, उपसमितियों और कार्यसमूहों के काम की समीक्षा की, जिसमें राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को शामिल किया गया है। चर्चा के बाद दोनों नेताओं ने कार्यवृत्त (मिनट्स) पर हस्ताक्षर किए।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान रक्षा साझेदारी — संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और रक्षा उद्योग में सहयोग सहित — में बढ़ी घनिष्ठता को दर्शाने हेतु परिषद् ने एसपीसी के तहत रक्षा सहयोग से संबंधित एक नई मंत्रिस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया।

सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच के पारस्परिक संबंधों, जिसमें हाल के वर्षों में उल्लेखनीय गति आई है, को मजबूत करने हेतु परिषद् ने एसपीसी के तहत पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग से संबंधित एक नई मंत्रिस्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया।

भारत-सऊदी अरब एसपीसी के तहत अब चार समितियां निम्नानुसार होंगीः

(1) राजनीतिक, दूतावास संबंधी एवं सुरक्षा सहयोग समिति
(2) रक्षा सहयोग समिति
(3) अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, निवेश और प्रौद्योगिकी समिति
(4) पर्यटन एवं सांस्कृतिक सहयोग समिति

निवेश से संबंधित उच्चस्तरीय कार्य बल

ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, फिनटेक, डिजिटल बुनियादी ढांचे, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, मैन्यूफैक्चरिंग और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए निवेश से संबंधित संयुक्त उच्चस्तरीय कार्य बल ने विविध क्षेत्रों में इस तरह के निवेश के प्रवाह को तेजी से बढ़ावा देने के लिए एक समझ विकसित की।

दोनों पक्ष भारत में दो रिफाइनरियां स्थापित करने में सहयोग करने पर सहमत हुए।

कराधान जैसे क्षेत्रों में एचएलटीएफ द्वारा की गई प्रगति भविष्य में निवेश संबंधी व्यापक सहयोग की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि है।

समझौता ज्ञापनों/समझौतों की सूची

- शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में सऊदी अंतरिक्ष एजेंसी और भारत के अंतरिक्ष विभाग के बीच समझौता ज्ञापन।
- सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।
- सऊदी अरब एंटी-डोपिंग कमेटी (एसएएडीसी) और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी, भारत (एनएडीए) के बीच एंटी-डोपिंग संबंधी शिक्षा एवं रोकथाम के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।
- सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन (एसपीएल) और भारत के संचार मंत्रालय के डाक विभाग के बीच इनवर्ड सरफेस पार्सल के संबंध में सहयोग से संबंधित समझौता। ■

पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब 2023-2024 में भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा। दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की

दोनों पक्षों ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस संदर्भ में दोनों पक्षों ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि यह मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। वे इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी कारण से किसी भी आतंकी कृत्य का कोई औचित्य नहीं हो सकता।

उन्होंने सीमा पार आतंकवाद की निंदा की और सभी देशों से दूसरे देशों के खिलाफ़ आतंकवाद के इस्तेमाल को अस्वीकार करने, जहां भी आतंकवाद का बुनियादी ढांचा मौजूद है, उसे नष्ट करने और आतंकवाद के अपराधियों को तुरंत न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने दूसरे देशों के खिलाफ़ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए मिसाइलों और ड्रोन सहित हथियारों तक पहुंच को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों पक्षों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सेमी-कंडक्टर आदि जैसे नए और उभरते क्षेत्रों सहित प्रौद्योगिकी में सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। डिजिटल शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए दोनों पक्ष इस क्षेत्र में सहयोग की संभावना तलाशने पर सहमत हुए। उन्होंने विनियामक और डिजिटल क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और सऊदी अरब साम्राज्य के संचार, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर भी संतोष व्यक्त किया। ■

छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम, रायगढ़ (महाराष्ट्र)

शिवाजी महाराज का मतलब स्वाभिमान और स्वराज की अमर जिजीविषा है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 12 अप्रैल को महाराष्ट्र के रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की 345वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़णवीस, उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे एवं श्री अजित पवार और केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि जहां हिन्दवी स्वराज का स्वर्ण सिंहासन प्रस्थापित हुआ, उस ऐतिहासिक रायगढ़ किले पर आना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक रायगढ़ किला बाल शिवा से लेकर छत्रपति के अंतिम समय तक के इतिहास का साक्षी है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दुस्तान के कण-कण में स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने हेतु एक अमर जिजीविषा पैदा की और देखते ही देखते चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ महाराष्ट्र हिन्दवी स्वराज में बदल गया।

शिवाजी महाराज के साथ न भाग्य था, न अतीत

श्री अमित शाह ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ न भाग्य था, न अतीत उनके साथ था और न ही धन एवं सेना उनके पास थी, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र दिया और देखते ही देखते 200 साल से चल रही मुगलशाही को चकनाचूर करने का काम किया। जब शिवाजी महाराज की सेना अटक, बंगाल, कटक और तमिलनाडु तक पहुंची, तब सभी को भरोसा हुआ कि देश, स्वधर्म, देश की भाषाएं और संस्कृति बच गई है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया में हर क्षेत्र में प्रथम बनाने की मूल कल्पना शिवाजी महाराज ने रखी थी। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 75 साल के बाद आज हम दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े हैं और संकल्प करते हैं कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब भारत दुनिया में हर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर होगा।

स्वधर्म पर अभिमान, स्वराज की आकांक्षा

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि स्वधर्म पर अभिमान, स्वराज की आकांक्षा और स्वभाषा को अमर बनाने के विचार मानव जीवन के स्वाभिमान के साथ जुड़े हैं। मानव जीवन के स्वाभिमान के इन तीन मूल चरित्र को शिवाजी महाराज ने देश और दुनिया के सामने रखा।

श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज ने प्रशासन के क्षेत्र में ढेर सारे सिद्धांत स्थापित किए। उनके अष्ट प्रधान मंडल की कल्पना को आज हमने कैबिनेट के रूप में अपनाया और कैबिनेट अष्ट प्रधान मंडल का ही विस्तृत स्वरूप है। उन्होंने कहा कि सत्तासीन लोगों द्वारा न्याय के लिए भी शिवाजी महाराज ने कई सिद्धांत प्रस्थापित किए। शिवाजी महाराज ने अपने काम से सुशासन का दृष्टांत प्रस्थापित करने का काम किया।

छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिन्दुस्तान के कण-कण में स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने हेतु एक अमर जिजीविषा पैदा की और देखते ही देखते चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ महाराष्ट्र हिन्दवी स्वराज में बदल गया

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि शिवाजी महाराज का अंतिम संदेश था कि स्वराज, स्वधर्म के सम्मान और स्वभाषा को अमर बनाने की लड़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज यह लड़ाई गौरव के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी जी ने भारत को पूरे विश्व में गौरवमय स्थान दिलाने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि शिवाजी महाराज का मतलब संकल्प, समर्पण, बलिदान, शौर्य, स्वाभिमान और स्वराज की अमर जिजीविषा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी को घर-घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिवाजी महाराज की राज मुद्रा को हमारी नौसेना का प्रतीक बनाकर पूरी दुनिया में घोषणा की है कि हमारा देश और हमारा स्वराज पूरी तरह सुरक्षित है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। ■

'आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी'

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 13 अप्रैल, 2025 को चेन्नई, तमिलनाडु में एनडीए की प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, एआईएडीएमके महासचिव एवं तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री एडप्पादी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु की भाजपा इकाई के वर्तमान अध्यक्ष श्री के अन्नामलाई सहित एनडीए एवं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। श्री शाह ने इस प्रेस वार्ता में एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने की घोषणा की।

श्री शाह ने कहा कि आज एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएम, भाजपा और सभी साथी दल मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे। यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में और तमिलनाडु राज्य स्तर एआईएडीएमके के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा।

एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईएडीएम, भाजपा और सभी साथी दल मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत लड़ेंगे

श्री शाह ने डीएमके पर हमला बोलते हुए कहा कि तमिलनाडु में डीएमके पार्टी सनातन धर्म और त्रिभाषा नीति जैसे मुद्दे केवल जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने के लिए उठा रही है। डीएमके सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। दलितों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है एवं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बद से बदतर होती जा रही है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार में 39 हजार करोड़ रुपए का शराब घोटाला, रेत खनन घोटाला, ऊर्जा घोटाला, एल कोट घोटाला, परिवहन घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग, पोषण किट घोटाला, फ्री धोती घोटाला, नौकरी के बदले गैस सिलेंडर घोटाला सहित तस्करी की घटनाएं भी सामने आई हैं और मनरेगा में भी घोटाला हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमिल भाषा, संस्कृति और तमिल जनता पर गौरव करती है और उनका सम्मान भी करती है। तमिलनाडु की महान परंपरा सेंगोल को संसद भवन में स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही किया। डीएमके ने कभी इसकी मांग तक नहीं की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत की। खेलो इंडिया में तमिल मार्शल आर्ट 'शिलम्बम' को भी उन्होंने ही शामिल किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 करोड़ की लागत से केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की स्थापना करवाई और अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल चेयर भी स्थापित करवाई। मोदी सरकार तिरुक्कुरल का अनुवाद अनेक भाषाओं में करवा रही है। इनमें से 63 भाषाओं में अनुवाद पूरा हो चुका है। महान तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के संपूर्ण रचनाओं के संग्रह का विमोचन भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि तमिलनाडु के युवा आईएएस और आईपीएस की परीक्षा तमिल भाषा में दे सकें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ही सीएपीएफ की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र तमिल भाषा में उपलब्ध कराए, जबकि पहले ये सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही होते थे। डीएमके के नेता केंद्र की सत्ता में भागीदार रहे लेकिन उन्होंने कभी इस कदम के बारे में नहीं सोचा।

उन्होंने कहा कि जहां-जहां भाजपा या एनडीए की सरकारें हैं, वहां मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषाओं में शुरू करवाई गई है लेकिन तीन वर्षों से मांग किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री स्टालिन ने तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू नहीं करवाई है। डीएमके ने तमिल भाषा के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। कांग्रेस क्यों चुप है?

श्री शाह ने कहा कि एआईएडीएमके एक प्रकार से 1998 से एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। लंबे समय तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती जयललिता ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है। श्री शाह ने 2026 में होने वाले तमिलानाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय और तमिलनाडु में एक बार पुनः एनडीए सरकार बनने पर विश्वास जताया। ■

नयनार नागेंद्रन बने तमिलनाडु प्रदेश भाजपाध्यक्ष

भाजपा विधायक श्री नयनार नागेंद्रन को 12 अप्रैल, 2025 को तमिलनाडु प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष चुना गया। केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी एवं भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुघ ने चेन्नई में पार्टी की एक बैठक में श्री नागेंथ्रन को तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित किया। ■

बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्र सर्वप्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के अग्रदूत

राजनाथ सिंह

हमारे संविधान निर्माता एवं अग्रणी राष्ट्र–निर्माताओं में से एक विभूति बाबासाहेब भीमराव रामजी आंबेडकर जी की आज 135वीं जयंती है। बाबासाहेब ने दलितों और हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया। बाबासाहेब समाज के कमजोर वर्गों के जनप्रिय नायक और संघर्ष के प्रतीक पुरुष हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन बाबासाहेब के योगदान और विरासत के साथ सबसे बड़ा अन्याय यह हुआ है कि उनको सिर्फ एक दलित नेता के रूप में सीमित कर दिया गया है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी बाबासाहेब को आधुनिक भारत के एक सबसे अग्रणी विचारक के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

यह सर्वविदित है कि स्कूल के दिनों में बाबासाहेब को उस नल से पानी पीने की अनुमति भी नहीं थी, जिससे नल से बाकी सब बच्चे पीते थे। ऐसे में अक्सर वह जितने वक्त स्कूल में रहते, प्यासे रहते थे। एक दिन, जब असहनीय प्यास के कारण उन्होंने इस अमानवीय प्रथा का उल्लंघन किया तो उन्हें न केवल अपमानित किया गया, बल्कि कठोर दंड भी दिया गया। जीवनपर्यंत ऐसे अनेक हृदय विदारक अनुभवों के बाद कोई भी सामान्य व्यक्ति या तो अपने भाग्य को कोसकर रह जाता या हिंसा का रास्ता चुनता। लेकिन बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने भीतर के गुस्से को सकारात्मक रूप देते हुए शिक्षा का मार्ग चुना। जिस समय उनके समाज के लोगों को शिक्षा लेने के अनुमति भी नहीं थी उस समय बाबासाहेब ने एमए, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, डीलिट और बार-एट–लॉ की उपाधियां हासिल कीं। उन्होंने कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित विदेशी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त की। डॉ. आंबेडकर महान समाज सुधारक तो थे ही वह उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, कानूनविद, अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने राजनीति, नैतिकता, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून और धर्मशास्त्र आदि व्यापक विषयों पर विस्तार से लिखा है। डॉ आंबेडकर के विचार, लेख और दर्शन पढ़कर उनकी विद्वता की विशालता का पता चलता है। उनके लेखन में जो नवीनता, गहन अध्ययन एवं चिंतन मिलता है वह विपुल है। वे अगर चाहते तो विदेश में आकर्षक वेतन प्राप्त करके अपना जीवन सुख और प्रतिष्ठा के साथ व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मातृभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया।

उनका यह भी मानना था कि चरित्र, शिक्षा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे मानते थे कि एक ऐसा शिक्षित व्यक्ति जिसमें चरित्र और विनम्रता की कमी हो, हिंसक जीव से भी अधिक खतरनाक होता है। और उसकी शिक्षा से यदि गरीबों की हानि हो तो वह व्यक्ति समाज के लिए अभिशाप है।

बाबासाहेब के चरित्र का एक और पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं वह है कि वे एक महान संस्थान निर्माता भी थे। आज भारत में आरबीआई और केंद्रीय जल आयोग जैसी कई संस्थाएं बाबासाहेब की दूरदर्शिता का ही परिणाम हैं। अर्थशास्त्र पर अपनी महारत के आधार पर उन्होंने भारत के सामने आने वाली मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण किया था। अपनी थीसिस में उन्होंने विस्तार से बताया था कि कैसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया फिक्सडएक्सचेंज सिस्टम (fixed exchange system) भारत में केवल अंग्रेजों के ही हितों की पूर्ति करता है। उनकी यही थीसिस भारतीय रिजर्व बैंक के निर्माण का आधार बनी।

बाबासाहेब का लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। उनका मानना था कि कोई भी राज्य तब तक लोकतांत्रिक नहीं हो सकता है, जब तक समाज लोकतांत्रिक न हो। उनका यह भी मानना था कि जब तक समाज में एक नैतिक व्यवस्था न हो, लोकतंत्र का विचार कल्पना ही रहेगा। यह भी कहा जा सकता है कि जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्य एक साथ सम्पूर्ण होते हैं उसी प्रकार लोकतंत्र, राजनीति और नैतिकता एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं।

बाबासाहेब मानते थे कि जहां भी सामाजिक व्यवस्था नैतिक और समतामूलक नहीं होंगी, उस समाज में लोकतंत्र जीवित ही नहीं रह पाएगा। गांधीजी की तरह, बाबासाहेब सामाजिक सुधार के लिए प्रतिबद्ध थे क्योंकि वह भारत के भविष्य, इसके लोकतंत्र और अर्जित स्वतंत्रता के बारे में बहुत चिंतित थे। उनकी आशंकाएं संविधान सभा में उनके अंतिम भाषण में व्यक्त हुईं हैं। इसमें बाबासाहेब ने कहा कि हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। उन्होंने चेतावनी दी थी कि हमारी अकर्मण्यता के कारण भारत एक बार फिर से अपना लोकतंत्र और स्वतंत्रता खो सकता है। पूना में अपने एक संबोधन में उन्होंने कहा था कि हमें एक लोकतांत्रिक संविधान मिला है लेकिन संविधान बनाकर हमारा काम पूरा नहीं हुआ बल्कि बस शुरू हुआ है।

संविधान के मुख्य निर्माता के तौर पर उनकी यह बात उनकी दूरदर्शी सोच की प्रमाण है। भारत लगभग आठ दशकों से बाबासाहेब द्वारा दिखाए गए लोकतंत्र के मार्ग पर अनवरत आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज कुछ लोगों द्वारा जाति, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर सामाजिक विभाजन का कुप्रयास किया जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये विभाजनकारी प्रयास कभी सफल न हों। इन कुचक्रों को समझने के लिए और रोकने के लिए, हमें डॉ. आंबेडकर को और अधिक पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए बाबासाहेब आर्यन-द्रविड़ विभाजन की असत्य

कल्पना का लाभ उठा सकते थे लेकिन उन्होंने आर्यन-द्रविड़ विभाजन और 'आर्यन इन्वेजन थ्योरी' को सिरे से नकार दिया था। बाबासाहेब ने 1918 में प्रकाशित एक शोधपत्र में लिखा था कि आर्यन या द्रविड़ विभाजन जैसी कोई बात होती है इस बात से ही भारत के लोग अनभिज्ञ थे। जब विदेशी स्कॉलर्स ने भारत में आकर इस प्रकार की विभाजन रेखाएं खींची तब यह विभाजन बना। अन्यत्र, उन्होंने कई उदाहरणों का हवाला दिया जहां यजुर्वेद और अथर्ववेद के ऋषियों ने शूद्रों के लिए मंगल बातें कही हैं और दिखाया है कि कई अवसरों पर 'शूद्र' परिवार में जन्में व्यक्ति भी राजा बने। उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था कि तथाकथित 'अस्पृश्य' लोग 'आर्यों' और 'द्रविड़ों' से नस्लीय रूप से भिन्न हैं।

इस सबके साथ ही जो लोग अपने संकीर्ण और सांप्रदायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए भाषा के मुद्दे का दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं, उन्हें राष्ट्र की एकता और इसमें एक भाषा की भूमिका पर डॉ. आंबेडकर के विचारों को पढ़ना चाहिए। 10 सितंबर, 1949 को उन्होंने संविधान सभा में एक संशोधन पेश किया जिसमें संस्कृत को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में समर्थन दिया गया था। 'भाषावार राज्यों के संबंध में विचार' में, बाबासाहेब ने कहा है, "भाषा, संस्कृति की संजीवनी होती है। चूंकि भारतवासी एकता चाहते हैं और एक समान संस्कृति विकसित करने के इच्छुक हैं, इसलिए सभी भारतीयों का यह भारी कर्तव्य है कि वे हिन्दी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। यदि मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता तो भारत, भारत कहलाने का पात्र नहीं रहेगा। वह विभिन्न जातियों का एक समूह बन जाएगा, जो एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ाई-झगड़े और प्रतिस्पर्धा में रत रहेगा।" यह ध्यान देने योग्य है कि बाबासाहेब मूल रूप से हिंदी भाषी नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सदैव राष्ट्र को सबसे पहले रखा।

22 दिसंबर, 1952 को पुणे में दिए अपने एक भाषण में डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र का स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं और 'आधुनिक लोकतंत्र' का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। इसी मूलमंत्र के साथ पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में सफल रही है। हमने लगभग 16 करोड़ घरों में जल पहुंचाने का काम किया है। हमने गरीब परिवारों के लिए लगभग 5 करोड़ घर बनवाए हैं।

वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएम–जनमन अभियान की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से हमारे PVTGs समुदायों के लोगों का व्यापक विकास किया जा रहा है और अनेक मूलभूत सुविधाओं को PVTG समुदाय के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2018 में 'आयुष्मान भारत' योजना की शुरुआत भी की गई है जिसके माध्यम से जन-जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्य संविधान और लोकतंत्र के प्रति हमारी समर्पण भावना और बाबासाहेब के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाते हैं।

डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के साथ राजनीतिक लोकतंत्र की कल्पना की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य बाबासाहेब के विजन के अनुरूप है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां बाबासाहेब की महान विरासत और योगदान के बारे में अधिक से अधिक जानें, हमारी सरकार द्वारा डॉ. आंबेडकर से जुड़े पांच स्थानों यानी 'पंच तीर्थ' को विकसित किया गया है।

पिछले महीने जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागपुर में दीक्षाभूमि का दौरा किया था, तो उन्होंने बाबासाहेब आंबेडकर के सपनों के भारत को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया था। बाबासाहेब की जयंती हम सभी भारतीयों द्वारा उनके द्वारा दिए गए मूल्यों और आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा को दोहराने का अवसर है। बाबासाहेब की विरासत को उचित सम्मान देने के लिए हमें उनके विचारों को आत्मसात् करना चाहिए और उन्हें एक समुदाय मात्र के नेता के रूप में नहीं बल्कि अग्रणी राष्ट्र–निर्माता और उत्कृष्ट बुद्धिजीवी के रूप में भी देखना चाहिए। बाबासाहेब ने कहा था, "आज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता सर्वसाधारण में साझा राष्ट्रीयता की भावना सृजित करना है, यह भावना नहीं कि वे पहले भारतीय हैं और बाद में हिन्दू-मुसलमान अथवा सिंधी हैं, परंतु यह कि पहले और अंततः भारतीय ही हैं।" उनको सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि हम सभी अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र, और पंथ से ऊपर उठकर 'भारतीय' बनें।

बाबासाहेब मां भारती के सच्चे सपूत और राष्ट्र-गौरव हैं। हम सभी धन्य हैं कि मां भारती ने हमें अपनी कोख में जन्म दिया लेकिन मां भारती धन्य हैं कि बाबासाहेब जी जैसे व्यक्ति ने उनकी कोख से जन्म लिया। आइए, आज 135 साल बाद हम उन्हें वह स्थान दें जिसके वे हकदार हैं और जिसे ब्रिटिश भारत और नव-स्वतंत्र भारत ने नहीं दिया— सर्वप्रथम और अंत तक भारतीय, राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के अग्रदूत और हमारे लिए वंदनीय बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। ■

(लेखक भारत के रक्षा मंत्री हैं)

बाबासाहेब आंबेडकर

सर्वसमावेशी समाज की स्थापना से सशक्त भारत के निर्माण तक

तरुण चुग

बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर जिनका सम्पूर्ण जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता की एक मिसाल है, ऐसे महानुभाव की जयंती केवल एक उत्सव पर्व नहीं, बल्कि उनके विचारों को याद करने और उन्हें जीवन में उतारने का अवसर भी है, उनका सम्पूर्ण जीवन ही शिक्षा और प्रेरणा से ओत-प्रोत है जो यह सीख देती है कि शिक्षा और आत्म-सम्मान किसी भी समाज को सशक्त और संगठित बना सकता है और उनका सम्पूर्ण जीवन इस बात का प्रमाण भी है कि दृढ़ संकल्प और ज्ञान द्वारा हर बाधा को पार किया जा सकता है।

भारतीय इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनका प्रभाव समय की सीमाओं को पार कर जाता है, ऐसे ही एक युगपुरुष डॉ. भीमराव आंबेडकर हैं, जिन्हें प्यार से 'बाबासाहेब' कहा जाता है। बाबासाहेब न केवल एक व्यक्ति थे, बल्कि एक विचारधारा थे जो सामाजिक न्याय, समानता और मानव गरिमा के लिए समर्पित थे। उनका सम्पूर्ण जीवन और विचार बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं दर्शन के क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बाबासाहेब ने अपने जीवन में असंख्य चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय समाज की दिशा और दशा दोनों बदल दी।

लोकतंत्र सिर्फ शासन की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता का आधार भी होना चाहिए, इस विचार को आत्मसात् कर बाबासाहेब ने भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, और न्याय जैसे मूल्यों को शामिल किया और संविधान को एक ऐसा आधार दिया जो सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने में सक्षम हो। देश में उनका योगदान सिर्फ संविधान निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति को एक समावेशी और प्रगतिशील दिशा प्रदान की, उनके विचार और कार्य आज भी भारतीय लोकतंत्र के मूल में हैं और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरणास्रोत बने हुए हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को सबसे बड़ी बाधा मानने वाले बाबासाहेब इसे समाप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे आज उनके विचारों की विरासत भारतीय राजनीति में समानता और मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है।

स्वतंत्र भारत में बाबासाहेब का योगदान बहुआयामी और गहरा है। उन्होंने संविधान निर्माण के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी मजबूत नींव प्रदान की। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्होंने संविधान को न केवल एक कानूनी दस्तावेज बल्कि सामाजिक क्रांति का माध्यम बनाया। बाबासाहेब का स्पष्ट मानना था कि संविधान की प्रभावशीलता अच्छे प्रशासकों की गुणवत्ता पर निर्भर है।

बाबासाहेब की दूरदर्शी सोच आज भारतीय लोकतंत्र की नींव है। उन्होंने संविधान को एक कानूनी दस्तावेज के साथ उसे भारत में सामाजिक क्रांति का माध्यम भी बनाया। उनका कहना था 'संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर इसे लागू करने वाले अच्छे न हों, तो यह बेकार है।' उनके विचार, आदर्श और सिद्धांत भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की ओर ले जाने वाले प्रकाश पुंज के समान हैं।

स्वतंत्र भारत की कामना के साथ-साथ बाबासाहेब ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी सर्वोपरि माना। इस विषय पर उनके विचार थे कि 'स्वतंत्रता के बिना समानता और भाईचारा संभव नहीं है।' देश के संविधान निर्माण में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उनके आदर्शों का केंद्र थे और संविधान में ये तीनों तत्व का शामिल होना उनके सिद्धांत-दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। सामाजिक समानता के पक्षधर बाबासाहेब ने जाति व्यवस्था को समाज का सबसे बड़ा अभिशाप माना और इसके उन्मूलन पर हमेशा ही जोर दिया। उनके विचार से 'जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता।' वंचितों के लिए शिक्षा को अति महत्वपूर्ण बताते हुए बाबासाहेब ने देश में वंचितों के उत्थान के लिए शिक्षा पर जोर दिया। 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो' उनका मूल मंत्र था। महिला सशक्तीकरण के लिए उनके विचार व प्रयास को कभी भुलाया नहीं जा सकता, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने पक्षधर बाबासाहेब ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से देश में महिलाओं को संपत्ति, तलाक और विवाह में अधिकार दिलाने का सार्थक प्रयास किया।

बाबासाहेब और कांग्रेस के विचार, दृष्टिकोण और प्राथमिकता में हमेशा ही मतभेद रहे क्योंकि कांग्रेस ने दलितों और वंचित वर्गों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने में कभी रुचि ही नहीं दिखाई। बाबासाहेब मानते थे कि कांग्रेस का भारत के दलित और वंचितों से कोई सरोकार नही। साथ में उनका यह भी मानना था कि कांग्रेस ने उनके सामाजिक सुधार के एजेंडे को जान-बूझकर कमजोर करने का काम किया और उनका केवल प्रतीकात्मक इस्तमाल किया और कभी उनके विचारों समर्थन नहीं किया। कांग्रेस सरकारों पर डॉ. अम्बेडकर को उनके कद और योगदान के अनुरूप सम्मान देने में जान-बूझकर देरी करने और उनकी

उपेक्षा करने के भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' को लेकर है। डॉ. अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण 1956 में हुआ था, लेकिन उन्हें भारत रत्न उनके महापरिनिर्वाण के 34 साल बाद 1990 में प्रदान किया गया वो भी तब जब देश में एक गैर-कांग्रेसी भाजपा समर्थित सरकार आई, संविधान शिल्पी के साथ कांग्रेस का ऐसा व्यवहार दुखद और पीड़ादायक है। उनके महापरिनिर्वाण पर भी कांग्रेस ने उपेक्षापूर्ण नीति का अनुसरण किया, तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू उनके अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हुए, सिर्फ इतना ही नहीं उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत दिल्ली में उन्हें अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए जगह तक नहीं दी कांग्रेस ने, उनके परिजनों को बाबासाहेब का पार्थिव शरीर मुंबई ले जाना पड़ा और इतना ही नहीं जिस विमान से बाबा साहेब को ले गए उसका भी किराया उनके परिजनों से लिया गया। बाबासाहेब और कांग्रेस के रिश्तों की विवेचना करें तो समझ आता है कि बाबासाहेब को उनके महापरिनिर्वाण के उपरांत भी सम्मान न देना, उनके प्रति कांग्रेस का भावनात्मक और प्रतीकात्मक उपेक्षा था जिसका कारण वास्तव में नेहरू-गांधी परिवार के पिछड़े वर्ग के प्रति भरा द्वेष था, जहां नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आरक्षण का विरोध किया था राजीव गांधी ने सदन के पटल पर ओबीसी आरक्षण का खुला विरोध किया था और अभी कुछ दिन पूर्व विदेश में जाकर राहुल गांधी ने आरक्षण को समाप्त करने की बात कही।

दूसरी ओर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बाबासाहेब के सम्मान और स्मृतियों को जीवंत किया गया। मोदी सरकार ने बाबासाहेब से जुड़े पंचतीर्थ (महू, लंदन, नागपुर, दिल्ली, मुंबई) स्थलों का व्यापक विकास किया। दिल्ली स्थित 'डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर' का निर्माण मोदी सरकार ने किया, जो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का उत्कृष्ट केंद्र बन चुका है। मोदी सरकार ने आंबेडकर जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया और बीएचआईएम एप, उनके लंदन आवास का स्मारक के रूप में विकास तथा उनकी रचनाओं का डिजिटलीकरण किया।

मोदी सरकार के कार्यों में बाबासाहेब के सिद्धांत साफ दिखते हैं। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक समानता लाती हैं। तीन तलाक और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे कानून बाबासाहेब की न्याय और मानवाधिकार की विचारधारा के अनुरूप हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों में बाबासाहेब के विचारों और आदर्शों का प्रभाव देखा जा सकता है, सामाजिक, समानता, आर्थिक सशक्तीकरण और समावेशी विकास के क्षेत्र में इसकी झलक साफ नजर आती है विशेषकर मोदीजी के जन कल्याणकारी योजनाओं में जैसे, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी अन्य योजनाओं में जिसके माध्यम से मोदी सरकार समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदीजी का देश में 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा डॉ. आंबेडकर के समानता और समावेशिता के सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है।

डॉ. भीमराव आंबेडकर का प्रारंभिक जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण है

प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टैंड-अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाएं वंचित वर्गों को आर्थिक और शैक्षिक अवसर प्रदान करती हैं जो बाबासाहेब के शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देने के अनुरूप है। बाबासाहेब, आर्थिक स्वतंत्रता को सामाजिक स्वतंत्रता की कुंजी मानते थे वे चाहते थे कि समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। मोदी सरकार का 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' इस विचार से मेल खाता है। मुद्रा योजना के जरिए छोटे उद्यमियों खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों को ऋण प्रदान करना, आंबेडकर के आर्थिक सशक्तीकरण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता नजर आता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पीएम किसान सम्मान निधि बाबासाहेब के उस विचार से जुड़ता है कि आर्थिक समानता सामाजिक बदलाव की आधारशिला है।

देश के युवाओं, खासकर वंचित एवं कमजोर वर्गों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने वाली प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की योजना 'स्किल इंडिया', डॉ. आंबेडकर के सभी को शिक्षा और आत्मनिर्भरता को अक्षरशः पूरा करती है। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति समावेशी शिक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देना वंचित समुदायों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में कदम है। एस.टी. एवं एस.सी. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन डॉ. आंबेडकर के विचारों से ही प्रेरित है। बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर भारतीय संविधान को लोकतंत्र का आधार मानते थे उनके ही विचार पथ पर चलते हुए मोदी सरकार ने देश में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने का कार्य किया है एवं संविधान और कानूनी ढांचे का सदैव सम्मान भी किया है। मोदी सरकार का देश के बाहर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सहारा देने वाला कानून 'नागरिकता संशोधन अधिनियम', डॉ. आंबेडकर के न्याय और मानवाधिकारों के विचारों से प्रेरित कहा जा सकता है। देश के मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला तीन तलाक कानून, बाबासाहेब के महिला सशक्तीकरण और समान नागरिक संहिता की वकालत से ही प्रेरित है।

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के विचार और सिद्धांत उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और कल भी प्रासंगिक ही रहेंगे, जो आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा और मार्गदर्शन करते रहेंगे। डॉ. भीमराव आंबेडकर का प्रारंभिक जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा का एक जीवंत उदाहरण है। सामाजिक भेदभाव और आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा और आत्म-सम्मान के प्रति जो जज्बा दिखाया, वह आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का विषय भी है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी हैं)

दिल्ली में 36 लाख लोगों को एबी पीएम-जेएवाई योजना का लाभ मिलेगा: जगत प्रकाश नड्डा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का शुभारंभ करके स्वास्थ्य सेवा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 अप्रैल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एनसीटी, दिल्ली सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय कॉर्पोरेट मामले तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री प्रवेश साहिब सिंह, दिल्ली के लोक निर्माण, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण तथा जल मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के उद्योग, खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री श्री आशीष सूद, दिल्ली के गृह, विद्युत, शहरी विकास, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री रविंदर सिंह तथा दिल्ली के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता मंत्री श्री रविंदर सिंह भी उपस्थित थे।

इस समारोह में संसद सदस्य (श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्री मनोज कुमार तिवारी, श्री योगेंद्र चंदोलिया और श्रीमती बांसुरी स्वराज) तथा दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी उपस्थित थे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एबी पीएम-जेएवाई दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में 62 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, "यह गर्व की बात है कि एबी पीएम-जेएवाई योजना से दिल्ली में 36 लाख लोग लाभान्वित होंगे।"

श्री नड्डा ने यह भी बताया कि दिल्ली में एबी पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन से 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत आ जाएंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 8.19 करोड़ लोग पहले ही इस योजना के तहत इलाज का लाभ उठा चुके हैं और सरकार ने इसके लिए कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 19 लाख लोग वंचित वर्ग के हैं जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कवरेज के बिना इन उपचारों का खर्च नहीं उठा सकते थे। उन्होंने आगे कहा, "आयुष्मान भारत योजना के परिणामस्वरूप आज जेब

से होने वाला खर्च 62 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत रह गया है।"

केंद्र सरकार के लिए स्वास्थ्य हमेशा से ही प्राथमिकता रहा है: रेखा गुप्ता

इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, "केंद्र सरकार के लिए स्वास्थ्य हमेशा से ही प्राथमिकता रहा है। स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार और गुणवत्तापूर्ण तथा किफायती दवाइयों को आम जनता तक पहुंचाने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा पोषण, योग, ध्यान आदि पर जोर दिया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र पर दिए जा रहे जोर को दर्शाता है।"

उन्होंने बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना अवधि के दौरान पीएम-एबीएचआईएम के तहत 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (एएएम) की स्थापना, 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) को मजबूत करने के लिए 1749 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के 30 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए। ये लाभार्थी केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली में इस योजना के लाभार्थी अब अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यह दिल्ली के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पीएम-एबीएचआईएम में शामिल होने से दिल्ली को लचीला, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा, जबकि एबी पीएम-जेएवाई के तहत दिल्ली में लाभार्थी परिवारों को योजना के तहत सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में हर साल 10 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर का लाभ मिलेगा। ■

'ओडिशा के लगभग 3.52 करोड़ लोग एबी-पीएमजेवाई के अंतर्गत कवर किए जाएंगे'

आयुष्मान भारत योजना के परिणामस्वरूप आज जेब से होने वाला खर्च 62 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत हो गया है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने 11 अप्रैल को कटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना के सह-ब्रांडेड कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर आयुष्मान वय वंदना योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम, ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मुकेश महालिंग और ओडिशा के सांसद एवं विधानसभा सदस्य भी उपस्थित थे।

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ओडिशा के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एबी पीएम-जेएवाई, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है जिसके तहत वर्तमान में 61 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो लगभग 1.3 करोड़ परिवारों, यानी ओडिशा के लगभग 3.52 करोड़ लोगों को जोड़ेगा।

> एबी पीएम-जेएवाई, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कवरेज कार्यक्रम है जिसके तहत वर्तमान में 62 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जो लगभग 1.3 करोड़ परिवारों, यानी ओडिशा के लगभग 3.52 करोड़ लोगों को जोड़ेगा

श्री नड्डा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 8.19 करोड़ से अधिक लोगों ने सेवाएं प्राप्त की हैं और देश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.26 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 61 करोड़ लोग कवर

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अब करीब 61 करोड़ लोग कवर हो चुके हैं। उन्होंने कहा, "पहले इस योजना के तहत 55 करोड़ से ज़्यादा लोग कवर होते थे। फिर आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और उनके परिवार यानी करीब 36 लाख लोगों को इस योजना में जोड़ा गया। पिछले साल अक्टूबर में 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को इस योजना के तहत कवर किया गया था और अब ओडिशा में आयुष्मान वय वंदना के लागू होने से 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, कवर हो जाएंगे।"

श्री नड्डा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के परिणामस्वरूप आज जेब से होने वाला खर्च 62 प्रतिशत से घटकर 38 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि 100-दिवसीय टीबी गहन उन्मूलन कार्यक्रम के तहत ओडिशा ने सक्रिय रूप से भाग लिया और 16,500 नए मामलों की पहचान की। उन्होंने कहा, "पीएम एबीएचआईएम के तहत ओडिशा के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,411 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।"

इस अवसर पर बोलते हुए श्री मोहन चरण माझी ने इस लॉन्च कार्यक्रम को 'ओडिशा की विकास गाथा में एक और उपलब्धि' बताया। उन्होंने कहा कि आज से ओडिशा के लाभार्थियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधा मिलेगी। राज्य के बाहर रहने वाले ओडिया लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। वे राज्य के बाहर के अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना से पूरे देश के लोगों, विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग को लाभ मिल रहा है।

श्री माझी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 4,000 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है तथा 5,000 से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया तथा राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य बताया।

श्री जुएल ओराम ने कहा कि इस योजना से ओडिशा के आदिवासियों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इस योजना के क्रियान्वयन से बहुत खुश हैं।

श्री मुकेश महालिंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के 3.50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड मिलेंगे और वय वंदना योजना के तहत ओडिशा के 23 लाख बुजुर्गों को भी लाभ मिलेगा। ■

प्रधानमंत्री ने 'भारत रत्न' बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि बाबासाहेब के सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' के निर्माण को शक्ति और गति प्रदान करेंगे।

एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा, "सभी देशवासियों की ओर से 'भारत रत्न' पूज्य बाबासाहेब को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। यह उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। उनके सिद्धांत एवं आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं।" ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बनें

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

जेद्दा (सऊदी अरब) में 22 अप्रैल, 2025 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जेद्दा (सऊदी अरब) में 22 अप्रैल, 2025 को रिट्ज–कार्लटन होटल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करता भारतीय समुदाय

नई दिल्ली में 21 अप्रैल, 2025 को प्रधानमंत्री आवास में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति श्री जेडी वेंस, द्वितीय महिला श्रीमती उषा वेंस एवं उनके बच्चों से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 17 अप्रैल, 2025 को दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, साथ में संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू

नई दिल्ली में 23 अप्रैल, 2025 को सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक की अध्यक्षता करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

मधुबनी (बिहार) में 24 अप्रैल, 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 03 मई, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

छायाकार: अजय कुमार सिंह